RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2019-2021 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com

www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 14 OCTOBER TO 20 OCTOBER 2020 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 06 ■ अंक 8 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

डाउनलोड स्पीड में 19.3 एमबीपीएस के साथ जियो सबसे तेज नेटवर्क, अपलोड स्पीड में वोडाफोन अव्वल : ट्राई Page 3

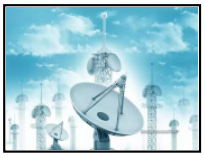

कोविड के दौर में खूब फला-फूला ड्राईफ्रूट्स और नट्स का बाजार Page 5

भारत की पहली ऑटोनोमस (लेवल1) प्रीमियम एसयीवी- MG GLOSTER लॉन्च Page 7

editoria!

छोटा पड़ेगा नया पैकेज

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था में आई जड़ता दूर करने और बाजार में नई मांग पैदा करने के लिए सोमवार को कई बड़े ऐलान किए। कुल मिलाकर 73 हजार करोड़ रुपये की छूटों, राहतों और अनुदानों के जरिए उनकी कोशिश यह है कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन के संयुक्त परिणाम के रूप में उपभोक्ताओं के बीच खर्च करने को लेकर बनी हुई हिचक किसी तरह टूटे और इकॉनमी की रुकी हुई गाड़ी आगे बढ़े। सरकार की इन घोषणाओं की टाइमिंग इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि दशहरा, दिवाली से लेकर छठ, क्रिसमस और न्यू ईयर तक का त्योहारी सीजन अब शुरू ही होने वाला है। दो-ढाई महीने की इस अवधि में खरीदारी को लेकर लोगों में विशेष उत्साह रहता है और इसी वजह से कारोबार जगत की इससे खास उम्मीदें लगी होती हैं। इस बार तो यह सीजन जैसे मंदी के कगार पर खड़ी अर्थव्यवस्था के लिए बचाव के आखिरी मौके के रूप में आया है। मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वित्त मंत्री द्वारा घोषित पैकेजों से यह उम्मीद की जा सकती है कि इससे अर्थव्यवस्था को इतना जोरदार धक्का मिल पाएगा, जिससे यह स्टार्ट होकर अपनी गति पकड़ सके। अगर इसका जवाब उत्साहपूर्ण हां में देना मुश्किल हो रहा है तो इसकी एक बड़ी वजह यह है कि इन घोषणाओं की धुरी केंद्र सरकार के कर्मचारियों तक सिमटी हुई है, जो आम उपभोक्ताओं का एक अत्यंत छोटा हिस्सा भर हैं। वित्त मंत्री ने यह उम्मीद जरूर जताई है कि केंद्र सरकार की ही तरह राज्य सरकारें और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां भी अगर अपने कर्मचारियों को एलटीसी में वैसी ही छूट दें तो बाजार में काफी पैसा पहुंच जाएगा। मगर ऐसी छूट देने के लिए उन्हें प्रेरित करने वाले किसी ठोस कदम की घोषणा का अभी इंतजार ही है। एक अलग कदम के रूप में राज्य सरकारों के लिए 50 साल के लिए ब्याजरहित लोन के रूप में जो 12,000 करोड़ रुपये दिए जाने की घोषणा की गई है उसमें भी इतनी सारी कैटिगरी बनाते हुए ऐसी शर्तें जोड़ दी गई हैं कि किस राज्य के पास कितना पैसा पहुंचेगा, कहना मुश्किल है। 1000 करोड़ रुपये किसी के भी हाथ नहीं आने वाले, इतना तय जान पड़ता है। इसमें दो राय नहीं कि मौजूदा हालात में सरकार के भी हाथ बंधे हुए हैं। महंगाई और राजकोषीय घाटे को काबू में रखने का दबाव उस पर है। ज्यादा खर्च करने के जोखिम को वह नजरअंदाज नहीं कर सकती। लेकिन इसके बरक्स खर्च न करने या जरूरत से कम खर्च करने का खतरा भी कम गंभीर नहीं है। फैक्ट्रियों में उत्पादन की स्थिति बताने वाले आईआईपी (इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉडक्शन) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक अगस्त महीने में इसमें पिछले साल के मुकाबले 8 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। साफ है कि जुलाई महीने में दर्ज की गई 10.8 फीसदी की गिरावट के मुकाबले हालात कुछ खास नहीं सुधरे हैं। यही स्थिति कुछ महीने और बनी रही तो इकॉनमी को मंदी के दलदल में फंसने से बचाना मुश्किल होता जाएगा। जाहिर है, कारगर कदम उठाने के लिए अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है।

केंद्र का बड़ा फैसला!

बुरे वक्त के लिए देश में यहां क्रूड ऑयल इकट्ठा करने को दी मंजूरी

नई दिल्ली। एजेंसी

कोरोना संकट के बीच क्रूड ऑयल की आपूर्ति में पैदा हुई रुकावटों से सबक लेते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. इसके तहत केंद्र ने देश में कच्चे तेल के नए रिजर्वायर्स (Crude Oil Reservoirs) बनाने को मंजूरी दे दी है। इन रिजर्वायर्स में मौजूद रिजर्व क्रूड ऑयल का सामरिक महत्व (Strategic Perspective) है। दरअसल, आपात स्थिति में कच्चे तेल का आयात नहीं होने के हालात में देश में क्रूड ऑयल का भंडार खत्म हो गया। फिलहाल देश के पास 12 दिन तक का स्ट्रैटजिक रिजर्व मौजूद है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया, 'कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है कि अब ओडिशा और कर्नाटक में भी जमीन के भीतर पथरीली गुफाओं में कच्चा तेल जमा किया जाएगा।

अप्रैल-मई 2020 में भारत ने क्रूड खरीदकर की 5000 करोड़ की बचत

पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राज्यसभा में एक सवाल का जवाब दिया था कि भारत ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कम कीमतों का फायदा उठाते हुए अप्रैल-मई, 2020 में 167 लाख बैरल क्रूड खरीदा है। इससे विशाखापत्तनम, मंगलुरु और पाडुर में बनाए गए सभी तीन रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व को भरा गया है. जनवरी 2020 के दौरान 4,416 रुपये प्रति बैरल की तुलना में कच्चे तेल की खरीद की औसत लागत 1398

रुपये प्रति बैरल थी। उन्होंने कहा है कि भारत ने अप्रैल-मई में 5 हजार करोड़ रुपये से अधिक की बचत की है। इसके साथ ही तीन रणनीतिक भूमिगत कच्चे तेल भंडार को भरने के लिए दो दशक से भी कम की अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतों का इस्तेमाल किया।

दुनिया के तीसरे बड़े तेल आयातक भारत ने किसी भी इमरजेंसी को पूरा करने के लिए तीन स्थानों पर अंडरग्राउंड रॉक केव्स में रणनीतिक भंडार बनाए हैं। नए अंडरग्राउंड स्टोरेज फैसिलटी बनने के बाद 22 दिन तक का रिजर्व भारत के पास होगा। यहां 65 लाख टन कच्चा तेल जमा रहेगा। दरअसल, देश में पहले से ऐसी तीन अंडरग्राउंड स्टोरेज फैसिलिटी मौजूद हैं। यहां 53 लाख टन कच्चा तेल हमेशा जमा रहता है। ये विशाखापत्तनम, मंगलुरु और पाडुर में है। ऑयल मार्केटिंग और प्रोडक्शन कंपनियां भी कच्चा तेल मंगाती हैं। हालांकि, ये स्ट्रैटेजिक रिजर्व इन कंपनियों के पास तेल के भंडार से अलग है। भारतीय रिफाइनरियों के पास आमतौर पर 60 दिन का स्टॉक रहता है. ये स्टॉक जमीन के अंदर मौजूद होते हैं।

पूर्व पीएम अटल बिहार वाजपेयी ने बनवाए थे अंडरग्राउंड स्टोरेज

भारत 1990 के दशक में खाड़ी युद्ध के दौरान लगभग दिवालिया हो गया था। उस समय तेल के दाम आसमान छू रहे थे। इससे पेमेंट संकट पैदा हो गया. भारत के पास सिर्फ तीन हफ्ते का स्टॉक बचा था। हालांकि, तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने स्थिति को संभाल लिया था। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति से अर्थव्यवस्था पटरी पर आई। इसके बाद भी तेल के दाम में उतार-चढ़ाव भारत को प्रभावित करते रहे। इस समस्या से निपटने के लिए 1998 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अंडरग्राउंड स्टोरेज बनाने का फैसला किया। इस समय इन गुफाओं की भंडारण क्षमता 53.3 लाख टन से ज्यादा है. लेकिन अभी इनमें 55 फीसदी तेल ही मौजूद है।

Loan Moratorium:

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा, आम आदगी की दीवाली आपके हाथ में है

नई दिल्ली। एजेंसी

सुप्रीम कोर्ट ने लोन मोरेटोरियम मामले पर आम आदमी को बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने कहा कि मोरेटोरियम सुविधा का फायदा लेने वाले लोगों को 15 नवंबर 2020 तक ब्याज पर ब्याज (Interest on Interest) नहीं देना होगा। साथ ही कहा कि 15 नवंबर तक किसी का लोन अकाउंट नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (NPA) घोषित नहीं किया जा सकता क्योंकि हमने इस पर रोक लगा रही है। इससे पहले सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार (Central Government) की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) व बैंकों के वकील हरीश साल्वे ने मामले की सुनवाई टालने का आग्रह किया। इसके बाद मामले की सुनवाई 2 नवंबर तक टाल दी गई है।

केंद्र को 2 नवंबर तक स्कीम पर सर्कुलर जारी करने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को ब्याज पर ब्याज माफी स्कीम को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए। इसके लिए केंद्र को एक महीने का वक्त क्यों चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही कहा कि अगर सरकार इस पर फैसला ले लेगी तो हम तुरंत आदेश पारित कर देंगे। इस पर सॉलीसीटर जनरल ने कहा कि सभी लोन अलग-अलग तरीके से दिए गए हैं। इसलिए सभी से अलग-अलग तरीके से निपटना होगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि ब्याज पर ब्याज माफी स्कीम को लेकर 2 नवंबर तक सर्कुलर लाया जाए। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सरकार 2 नवंबर तक ब्याज पर ब्याज माफी स्कीम को लेकर सर्कुलर जारी कर देगी।

तीन दिनों में पहली बार रुपये में तेजी, डॉलर के मुकाबले चार पैसे का सुधार

मुंबई। एजेंसी

एशियाई मुद्राओं में तेजी के रुख तथा घरेलू शेयरों दिन में लिवाली बहाल होने विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपये के प्रति धारण सुधरी और भारतीय मुद्रा अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले चार पैसे की बढ़त के साथ 73.31 पर बंद हुई। रुपया शुरू में दबाव में चल रहा था। अंतरबैंक विदेशी विनिमय बाजार में रुपया/डालर दर में एक सीमित दायरे में घट-बढ़ हुई। रुपया 73.39 पर खुला और कारोबार के अंत में डॉलर के मुकाबले चार पैसे की मजबूती के साथ 73.31 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। मंगलवार को बंद भाव 73.35 रुपये प्रति डॉलर था। कारोबार के दौरान विनिमय दर में 73.28-73.47 के दायरे में घट-बढ हुई। इस बीच छह प्रमुख मुद्राओं के समक्ष डॉलर की घट-बढ़ दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.06 प्रतिशत कमजोर होकर 93.47 रह गया। वैश्विक वायदा बाजार में ब्रेंट कच्चा तेल 0.09 प्रतिशत की तेजी के साथ 42.49 डॉलर प्रति बैरल हो गया। तीस शेयरों पर आधारित बंबई शेयर सूचकांक कारोबार के अंत में 169.23 अंकों की तेजी के साथ 10,794.74 अंक पर बंद हुआ। शेयर बाजारों के आंकड़ों के अनुसार विदेशी निवेशकों ने बुधवार को भारतीय बाजार में शुद्ध रूप से 821.86 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।

पश्चिमी तट में प्रस्तावित रिफाइनरी की क्षमता कम नहीं होगी, बीपीसीएल का निजीकरण रास्ते पर: प्रधान

नयी दिल्ली। एजेंसी

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने मंगलवार को कहा कि देश के पश्चिमी तटीय क्षेत्र में प्रस्तावित सालाना छह करोड टन क्षमता की तेल शोधन परियोजना में कमी करने का विचार नहीं है। उन्होंने कहा कि भविष्य के लिए इसकी जरूरत है। प्रधान ने कहा कि भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के निजीकरण का काम भी पटरी पर है, हालांकि कंपनी के आकार को देखते इस काम में सावधानी के साथ कदम उठाए जा रहे हैं। बीपीसीएल में सरकार अपनी पूरी 51.11 प्रतिशत हिस्सेदारी बेच रही है। प्रधान ने एनर्जी इंटेलिजेंस फोरम 2020 को संबोधित करते हुये कहा कि देश में ईंधन की मांग 2021 कैलेंडर वर्ष की पहली तिमाही (जनवरी- मार्च) के दौरान कोविड- 19 से पहले के स्तर पर पहुंच जाने का अनुमान है। उन्होंने कहा, "भारत की तेल रिफाइनिंग की मौजूदा क्षमता सालाना 25 करोड़ टन के आसपास है। अगले एक दशक में हम इसमें 10 करोड़ टन और जोड़ना चाहते हैं। हमारी मांग को देखते हुये 2030 तक हमारे पास 35 करोड़ टन रिफाइनिंग की क्षमता होनी चाहिये।" दुनिया के तीसरे सबसे बड़े पेट्रोलियम पदार्थों के उपभोक्ता देश भारत की ईंधन की खपत 2050 तक दुगुनी होने का अनुमान है। यह स्थिति नवीनीकरण और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का इस्तेमाल होने के बावजूद होने का अनुमान लगाया गया है। बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहन आने के बावजूद ईंधन की खपत बढ़ने का अनुमा है। प्रधान ने कहा कि निकट भविष्य में हाइड्रोकार्बन पर भारत की निर्भरता बनी रहेगी और भविष्य की मांग को पूरा करने के लिये पश्चिमी तटीय क्षेत्र में बनाई जाने वाली रिफाइनरी जरूरी है। उन्होंने कहा, "हम इस मामले में क्रियान्वयन के समय कुछ पीछे चल रहे हैं। यह स्थिति आर्थिक मुद्दों की वजह से नहीं बल्कि कुछ स्थानीय मुद्दों के कारण है। हम रिफाइनरी के आकार को लेकर पुनर्विचार करने नहीं जा रहे हैं।" उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण की वजह से परियोजना में देरी हो रही है और रिफाइनरी को बनाने वाली मुख्य प्रवर्तक कंपनी उपयुक्त स्थान पर जमीन उपलब्ध कराने को लेकर महाराष्ट्र सरकार से बातचीत कर रही है। जमीन का यह मुद्दा जल्द ही सुलझा लिया जायेगा। इस प्रमुख रिफाइनरी परियोजना को पहले रत्नागिरी क्षेत्र में लगाया जाना था लेकिन यहां भूमि अधिग्रहण में अड़चन आने के कारण इसके लिये वैकल्पिक स्थान की तलाश की जा रही है। इस रिफाइनरी में सउदी अरामको और अबु धाबी नेशनल आयल कंपनी ने मिलकर 50 प्रतिशत हिस्सेदारी ली है और इसे मूल रूप से 2024- 25 तक तैयार किया जाना था। बीपीसीएल में सरकार का अपनी पूरी 51.11 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव है। प्रधान ने कहा कि निजीकरण सरकार के एजेंडा में बरकरार है, हालांकि सरकार इस मामले में विनिवेश के आकार को देखते हुये सावधानी से आगे बढ़ रही है। बीपीसीएल के मामले में सरकार पहले ही शुरुआती बोली लगाने की समयसीमा को चार बार आगे बढ़ा चुकी है। अब रुचि व्यक्त करने की समयसीमा अगले महीने है। मौजूदा मूल्य पर बीपीसीएल में सरकार की हिस्सेदारी का मूल्य 37,600 करोड़ रुपये तक बैठता है। इसके बाद खरीदार को सार्वजनिक शेयरधारकों से 26 प्रतिशत अतिरिक्त शेयरों की खरीद करनी होगी जिसपर 19,000 करोड़ रुपये और खर्च हो सकते हैं।

भारत, ऑस्ट्रेलिया के बीच भूजल प्रबंधन के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी

नयी दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षमता निर्माण, अनुसंधान एवं विकास और सतत भूजल प्रबंधन को असरदार बनाने में सहयोग के लिए बुधवार को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी प्रदान कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस आशय की जानकारी दी। एक सरकारी बयान में कहा गया कि केन् द्रीय मंत्रिमंडल को केन् द्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब् ल् यूबी), जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, भारत और मैनेजिंग ऐक्वाफर रिचार्ज एंड सस् टेनिंग ग्राउंड वॉटर यूज थ्रू विलेज लेवल इंटरवेंशन (एमएआरवीआई) पार्टनर्स, ऑस् ट्रेलिया के बीच अक्टूबर, 2019 में हुए समझौता ज्ञापन (एमओयू) से अवगत कराया गया। बयान के मुताबिक, "इस समझौता ज्ञापन पर कृषि, शहरी, औद्योगिक और पर्यावरण संबंधी उद्देश् यों के लिए जल सुरक्षा अर्जित करने के वास्ते धरातल और भूजल प्रशिक्षण, शिक्षा और अनुसंधान में सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हस्ताक्षर किए गए हैं।"

अदाणी गैस ने कीमत कम करने की घोषणा की

सीएनजी और घरेलू पीएनजी के क्रमशः रु 1.75/किलोग्राम और रु. 1.11/एससीएम तक कीमतें कम कीं

अहमदाबाद। आईपीटी नेटवर्क

अदाणी ग्रुप के सिटी गैस डिस्ट्रिब्यूशन व्यवसाय, अदाणी गैस लिमिटेड (एजीएल), ने देश के अपने विभिन्न क्षेत्रों में कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) और घरेलू पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) की कीमतों में कमी की घोषणा करते हुए खुशी जाहिर की है।कीमतों में कमी 10 अक्टूबर 2020 से प्रभावी है। उत्तर प्रदेश के खुर्जा भौगोलिक क्षेत्र में सीएनजी की कीमतों में 1.75 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी की गई है। महेंद्रगढ़ में 1.70 रुपये प्रति किलोग्राम कमी की गई है, जबकि फरीदाबाद और पलवल क्षेत्रों में यह कमी 1.60 रुपये प्रति किलोग्राम की गई है, और गुजरात में अहमदाबाद/वडोदरा क्षेत्रों में 1.31 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी की गई है।

फरीदाबाद, पलवल और खुर्जा भौगोलिक क्षेत्रों में घरेलू पीएनजी की कीमतों में 1.11 रुपये प्रति एससीएम और अहमदाबाद तथा वडोदरा भौगोलिक क्षेत्रों में 1.0 रुपये प्रति एससीएम की कमी की गई है। सीएनजी और

घरेलू पीएनजी की कीमतों में कमी के साथ-साथ हमारे संशोधित कीमतों के बारे में विवरण नीचे दी गई तालिका में दिए गए हैं। इन सभी मूल्यों में टैक्स शामिल हैं। पहले से ही आकर्षक सीएनजी की कीमतों में कमी के साथ, उपभोक्ता अब पेट्रोल और डीजल के मुकाबले बहुत अधिक बचत कर पायेंगे (कुछ भौगोलिक क्षेत्रों में पेट्रोल की तुलना में 50₹ तक की बचत)। जहां एजीएल संचालित होता है, कीमतों में कटौती इन भौगोलिक क्षेत्रों में सभी निवासियों को भी अपने वाहनों को पर्यावरण के अनुकूल सीएनजी में परिवर्तित करने और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। एजीएल ने सुरक्षा पर ध्यान बढ़ाया है और ग्राहक इन चुनौतीपूर्ण समय में भी संपर्क-रहित घरेलू पीएनजी सेवाओं की स्वस्थ, विश्वसनीय और बेहतर सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। अदाणी गैस लिमिटेड के लगभग 4.50 लाख पीएनजी (घरेलू, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल) ग्राहक हैं और यह विभिन्न स्थानों पर 134 सीएनजी स्टेशनों के जरिये रिटेल सीएनजी ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करता है।

IMF Report: इस साल बांग्लादेशियों से भी कम हो जाएगी भारतीयों की कमाई!

नई दिल्ली। एजेंसी

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के मुताबिक इस वित्त वर्ष के दौरान भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी (Per Capita GDP) में 10.3 फीसदी की गिरावट आएगी। अगर यह अनुमान सही साबित हुआ तो प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में भारत बांग्लादेश से नीचे चला जाएगा। मंगलवार को जारी आईएमएफ (International Monetary Fund) की रिपोर्ट World Economic Outlook के मुताबिक 31 मार्च, 2021 को खत्म हो रहे इस वित्त वर्ष के दौरान भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी 10.3 फीसदी की गिरावट के साथ 1877 डॉलर रह जाएगी। आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक पड़ोसी बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति जीडीपी 2020 में 4 फीसदी बढ़कर 1,888 डॉलर पहुंचने का अनुमान है। इससे पहले जून में आईएमएफ ने इसमें 4.5 फीसदी गिरावट का अनुमान लगाया था। लेकिन एशिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी भारत के अगले वित्त वर्ष में 8.8 फीसदी की आर्थिक विकास दर हासिल करने की उम्मीद है। इससे तरह भारत एक बार फिर सबसे तेजी से बढ़ने वाली उभरती इकॉनमी का तमगा हासिल कर लेगा। इस दौरान चीन की विकास दर 8.2 फीसदी रहने का अनुमान है।

ग्लोबल अर्थव्यवस्था में 4.4 फीसदी गिरावट

आईएमएफ की रिपोर्ट में बताया गया है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान ग्लोबल अर्थव्यवस्था में 4.4 फीसदी की गिरावट आ सकती है। साल 2021 में इसमें 5.2 फीसदी की जोरदार वृद्धि दर्ज हो सकती है। आईएमएफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2020 के दौरान दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में केवल चीन ही एकमात्र देश होगा जिसकी जीडीपी में 1.9 फीसदी की वृद्धि दर्ज की जाएगी।

अटल रियलटेक लिमिटेड ने आईपीओ लॉन्च किया

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

अटल रियलटेक लिमिटेड ने आईपीओ लॉन्च किया। 2012 में शामिल हुई अटल रियलटेक लिमिटेड एक निर्माण कंपनी है, जो मुख्य रूप से विभिन्न सरकारी और निजी परियोजनाओं के अनुबंध और उप-अनुबंध करती है। अटल रियलटेक लिमिटेड (ARL) इस सप्ताह में ही SME IPO के माध्यम से कैपिटल मार्केट में प्रवेश कर रही है। यह 10 रुपए प्रति शेयर कीमत के 15, 04, 000 इक्विटी शेयर जारी करेगी, जिसमें हर शेयर का निश्चित मूल्य 72 रुपए होगा। इसके माध्यम से कंपनी 10 .83 करोड़ रुपए अर्जित करेगी। कंपनी का इश्यू फ़िलहाल खुला है और 7 अक्टूबर, 2020 को बंद होगा। ग्राहकों को कम से कम 1600 शेयर खरीदना अनिवार्य है, इससे अधिक शेयर लेने के इच्छुक आगे गुणकों में शेयर खरीद सकते हैं। आवंटन के बाद, शेयरों को एनएसई एसएमई एमर्ज प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध किया जाएगा। आर्यमान फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और गैलेक्टिको कॉरपोरेट सर्विसेज लिमिटेड, इश्यू के लीड मैनेजर हैं और बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इश्यू की रजिस्ट्रार है। आर्यमन कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड इस कंपनी के लिए मार्केट मेकर के रूप में काम कर रही है। वित्तवर्ष 2020 के लिए, कंपनी ने 2.62 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ और 58.69 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है। पिछले तीन फिस्कलस के लिए, ARL ने औसत रुपये 5.45 का EPS और 11.72% का औसत RoNW पोस्ट किया है। अटल रियलटेक लिमिटेड एक निर्माण कंपनी है, जो एकीकृत सिविल कार्य अनुबंध और इंजीनियरिंग सेवाएं प्रदान करती है, 31 मार्च 2020 तक 59.07 रुपए NOV के आधार पर इसके इशू की कीमत रुपये के पी / बीवी पर 1.22 रुपये है। यह महाराष्ट्र सरकार के साथ पंजीकृत कांट्रेक्टर है। I-A श्रेणी में काम करने वाली अटल रियलटेक लिमिटेड एक ऐसी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो स्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर प्रोजेक्ट्स के लिए एकीकृत सिविल कार्य अनुबंध और इंजीनियरिंग सेवाएं प्रदान करती है और महाराष्ट्र लोक निर्माण विभाग में I-A श्रेणी में एक रजिस्टर्ड कांट्रेक्टर है।

डाउनलोड स्पीड में 19.3 एमबीपीएस के साथ जियो सबसे तेज नेटवर्क, अपलोड स्पीड में वोडाफोन अव्वल : ट्राई

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

रिलायंस जियो एक बार फिर औसत 4 जी डाउनलोड स्पीड में अव्वल साबित हुई है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के सितंबर माह के आंकड़ों के मुताबिक जियो की औसत डाउनलोड स्पीड 19.3 मेगाबिट प्रति सेकंड (एमबीपीएस) मापी गई। डाउनलोड स्पीड के मामले में 8.6 एमबीपीएस के साथ आइडिया सेल्युलर नेटवर्क (अब वोडाफोन आइडिया) दूसरे स्थान पर है। ट्राई के 10 अक्टूबर को अद्यतन आंकड़ों के अनुसार वोडाफोन की डाउनलोड स्पीड 7.9 एमबीपीएस तथा भारती एयरटेल की 7.5 एमबीपीएस दर्ज की गई। हालांकि, वोडाफोन और आइडिया के मोबाइल कारोबार का विलय हो चुका है, लेकिन ट्राई ने उनके प्रदर्शन का आकलन अलग-अलग किया है। दोनों कंपनियों के नेटवर्क का एकीकरण अभी चल रहा है। इस रिपोर्ट से पहले पिछले महीने निजी कंपनी ने ओपनसिग्नल ने 49 शहरों के आधार पर एक अध्ययन जारी किया था जिसमें भारती एयरटेल को सबसे अधिक डाउनस्पीड वाली कंपनी घोषित किया गया था। ट्राई द्वारा औसत गति की गणना माईस्पीड एप्लिकेशन की सहायता से तत्काल आधार पर जुटाए गए आंकड़ों से की जाती है। ट्राई के आंकड़ों के

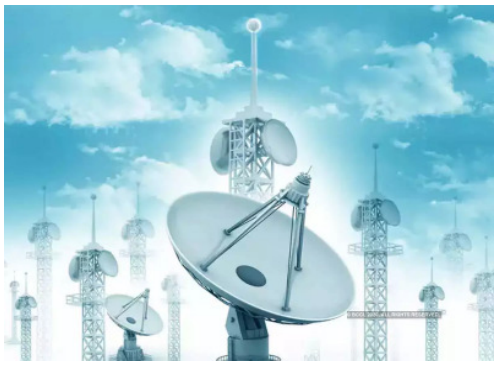

अनुसार सभी निजी दूरसंचार ऑपरेटरों की औसत गति अगस्त की तुलना में सितंबर में बढ़ी है। रिलायंस जियो नेटवर्क की डाउनलोड स्पीड सितंबर में 21 प्रतिशत बढ़कर 19.3 एमबीपीएस रही है। यह अगस्त के मुकाबले 3.4 एमबीपीएस अधिक है। अगस्त में रिलायंस जियो की 4जी डाउनलोड स्पीड 15.9 एमबीपीएस थी। ट्राई के अनुसार सितंबर में भारती एयरटेल के प्रदर्शन में भी सुधार हुआ है। एयरटेल के नेटवर्क पर डाउनलोड स्पीड सात प्रतिशत के सुधार के साथ 7.0 एमबीपीएस के मुकाबले सितंबर में 7.5 एमबीपीएस रही है। वोडाफोन और आइडिया के नेटवर्क पर डाउनस्पीड में 1-3 प्रतिशत का सुधार हुआ है। डाउनलोड स्पीड से विभिन्न ऐप से सामग्री को डाउनलोड किया जा सकता है। वहीं अपलोड स्पीड से फोटो और वीडियो को साझा किया जा सकता है। अपलोड स्पीड के मामले में वोडाफोन 6.5 एमबीपीएस के साथ सबसे आगे रही है। आइडिया की औसत अपलोड स्पीड 6.4 एमबीपीएस, भारती एयरटेल और जियो नेटवर्क दोनों की 3.5 एमबीपीएस रही है।

तेजी हो रहे डिजिटलीकरण के मद्देनजर भारत-आसियान के बीच साइबर क्षेत्र में सहयोग की जरूरत : अधिकारी

नयी दिल्ली। एजेंसी

विदेश मंत्रालय की एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकी पर तेजी से बढ़ती निर्भरता और कोविड-19 महामारी के मद्देनजर भारत और आसियान के बीच साइबर मंच को ' दुर्भावना रखने वाले किरदारों' से सुरक्षित करने के उपायों को मजबूत करने और सहयोग करने की जरूरत है। मंत्रालय में सचिव (पूर्वी मामले) रीवा गांगुली दास ने कहा कि कोविड-19 महामारी की वजह से 'डिजिटलीकरण' में तेजी आई है और साइबर क्षेत्र में हमारा जुड़ाव- घर से काम करना नयी परिपाटी बन गया है। 'आसियान-इंडिया ट्रैक 1.5 साइबर संवाद' के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नकद के कम इस्तेमाल से डिजिटल भुगतान पर निर्भरता बहुत बढ़ गई है। दास ने कहा, ''बड़े पैमाने पर आकंड़ों को ऑनलाइन साझा करने का काम हो रहा है। सोशल मीडिया की उपस्थिति बढ़ रही है। गतिमान और स्थायी आर्थिक विकास को पटरी पर लाने के लिए आपूर्ति तंत्र को चालू रखने में डिजिटल प्रौद्योगिकी अहम भूमिका निभा रही है।'' उन्होंने कहा, ''डिजिटल प्रौद्योगिकी पर हमारी बढ़ती निर्भरता और साइबर मंच का इस्तेमाल करने वालों की तेजी से बढ़ती संख्या के मद्देनजर ' दुर्भावना रखने वाले किरदार' से हमारे साइबर डोमेन को सुरक्षित रखने के लिए कदमों को मजबूत करने की जरूरत है।''

घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या सितंबर में 39.43 लाख रही, पिछले साल से 66 प्रतिशत कम: डीजीसीए

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या सितंबर में 39.43 लाख रही। यह पिछले साल इसी माह के मुकाबले 66 प्रतिशत कम है। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने बुधवार को यह जानकारी दी। डीजीसीए ने कहा कि इस साल जुलाई में 21.07 लाख और अगस्त में 28.32 लाख लोगों ने घरेलू हवाई यात्रा की। समीक्षावधि में इंडिगो से करीब 22.66 लाख यात्रियों ने यात्रा की और घरेलू विमानन बाजार में उसकी कुल हिस्सेदारी 57.5 प्रतिशत रही। वहीं स्पाइसजेट से उड़ान भरने वाले यात्रियों की संख्या 5.3 लाख रही और कंपनी की बाजार हिस्सेदारी 13.4 प्रतिशत रही। डीजीसीए के आंकड़ों के मुताबिक सितंबर में एअर इंडिया, एयरएशिया इंडिया, विस्तार और गोएयर से क्रमशः 3.72 लाख, 2.35 लाख, 2.58 लाख और 2.64 लाख यात्रियों ने उड़ान भरी। देश की छह प्रमुख विमानन कंपनियों की कुल उपलब्ध सीटों के मुकाबले यात्रियों से भरने की दर 57 से 73 प्रतिशत के बीच रही। डीजीसीए ने कहा कि, '' लॉकडाउन के बाद उड़ान सेवाएं दोबारो चालू होने से अब तक मांग में बढ़त देखी गयी है और इसलिए कंपनियों की सीटें भरने की स्थिति में सितंबर में सुधार हुआ है।'' इस दौरान स्पाइसजेट ने 73 प्रतिशत भरी सीटों के साथ उड़ान भरी। जबकि विस्तार, इंडिगो, एयरएशिया इंडिया, एअर इंडिया और गोएयर की सीटें भरने की दर क्रमशः 66.7 प्रतिशत, 65.4 प्रतिशत, 58.4 प्रतिशत, 57.9 प्रतिशत और 57.6 प्रतिशत रही। डीजीसीए ने कहा कि बेंगलुरू, दिल्ली, हैदराबाद और मुंबई जैसे देश के चार प्रमुख हवाईअड्डों पर एयरएशिया इंडिया की सबसे अधिक उड़ानें समय से चली। कंपनी की समयबद्धता 98.4 प्रतिशत रही। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए देश में 24 मार्च से लॉकडाउन लगाया गया था। इसके चलते घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगा दी गयी थी। करीब दो माह के अंतराल के बाद सरकार ने 25 मई से दोबारा घरेलू उड़ानों के परिचालन को अनुमति दे दी। वहीं लॉकडाउन के दौरान भी प्रवासियों की स्वदेश वापसी के लिए वंदे भारत मिशन के तहत विशेष अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन किया गया। वर्तमान में कुछ देशों के साथ अलग-अलग द्विपक्षीय समझौतों (एयर बबल पैक्ट) के तहत अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन किया जा रहा है।

सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का पीएम स्वनिधि के तहत अपने पहले ऋण का वितरण

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

देश में सबसे तेजी से विकसित हो रहे स्मॉल फाइनेंस बैंकों में से एक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक (एएइँ) ने पीएम एसवीए निधि योजना के तहत अपने पहले ऋण के वितरण की घोषणा की। इस योजना के प्रावधान के अनुरूप, 'श्रीमती आशा अशोक वाल्मीकि' को 10000/- रुपये का लोन दिया गया, जो पेशे से 'एक सब्जी विक्रेता' हैं। बैंक ने यह सुनिश्चित किया कि, लोन को मंजूरी देने तथा लोन के पैसे की निकासी की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और परेशानी मुक्त हो।

इस मौके पर सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी एवं सीईओ, श्री आर. बास्कर बाबू ने कहा, 'हमें इस बात का गर्व है कि, हम माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप पीएम स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी-पटरी वालों को छोटे पूंजीगत ऋण उपलब्ध कराने की मुहिम का हिस्सा बन चुके हैं। इस योजना का उद्देश्य एक आत्मनिर्भर परिवेश का निर्माण करना तथा इस महामारी से उत्पन्न संकट के बाद उनकी जिंदगी को पटरी पर लाने में मदद करना है। हमने हमेशा से अपने ग्राहकों को विश्वस्तरीय बैंकिंग सुविधाओं का अनुभव प्रदान करने, तथा उन्हें पूरी तरह आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने में मदद करने का प्रयास किया है। महामारी के इस दौर में सरकार ने आगे बढ़कर सबसे ज्यादा प्रभावित लोगों और व्यवसायों के लिए विभिन्न पहलों की घोषणा की है, और हमें खुशी है कि हमने अपने स्तर से इस मुहिम में योगदान दिया है।' सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, अपनी स्थापना के बाद से ही विभिन्न प्रकार के वित्तीय उत्पादों और सेवाओं को लगातार विकसित कर रहा है और इसे बेहतर बना रहा है ताकि बैंकिंग की सुविधाओं से वंचित लोगों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। इसके अलावा, बैंक की ओर से उन्हें बचत एवं निवेश के विभिन्न विकल्पों, सरकारी बीमा योजनाओं तथा डिजिटल बैंकिंग के अलग-अलग माध्यमों के बारे में शिक्षित किया जा रहा है।

SURYODAY
A BANK OF SMILES

आरबी बीएसआई अभियान ने छः सालों में 14 मिलियन लोगों की जिंदगी में सुधार लाया

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

दुनिया की अग्रणी कंज़्यूमर हैल्थ एवं हाईज़ीन कंपनी, रेकिट बेंकाईज़र ने अपने फ्लैगशिप बीएसआई कैम्पेन के साथ मौजूदा कोविड-19 महामारी से लड़ाई में हाईज़ीन व हैल्थ के प्रयासों में मदद करने के लिए अपना सामाजिक निवेश 10 मिलियन पाउंड से बढ़ाकर 20 मिलियन पाउंड करने का संकल्प लिया। पिछले छः सालों में यह अभियान भारत में 14 मिलियन लोगों को लाभान्वित कर चुका है। अभियान के एम्बेसडर, अमिताभ बच्चन के साथ इस साल यह अभियान भारतीयों को खुद की देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित करेगा ताकि एक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित हो।

कोरोना महामारी ने हैल्थकेयर के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव ला दिया है। हैल्थ, हाईज़ीन एवं सैनिटेशन लोगों की जिंदगी में अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया मूवमेंट द्वारा शुरू किए गए नेशनल डिजिटल हैल्थ मिशन (एनडीएचएम) के अनुरूप, आरबी बीएसआई अगले कुछ सालों में अंतिम छोर तक हैल्थ एवं हाईज़ीन पहुंचाने के लिए मजबूत सुधार करेगा। ये अभियान बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं, उचित सैनिटाईज़ेशन एवं पर्याप्त पोषण पर केंद्रित होंगे तथा सतत विधियों द्वारा पर्यावरण की रक्षा करेंगे।

यह अभियान कोरोना महामारी के बीच गंभीर होती मौजूदा पर्यावरण की परिस्थितियों को बनाए रखते हुए सतत विधियां प्रदान करने पर केंद्रित है। डेटॉल 100 प्रतिशत रिसाईकल्ड बोतल के लॉन्च के साथ डेटॉल हैंडवॉश की बोतल में जर्म प्रोटेक्शन के साथ उन उपभोक्ताओं तक पहुंच रहा है, जो पर्यावरण का ध्यान रखते हैं।पिछले साल हमारा अभियान 'स्वच्छ से स्वस्थ' की ओर बढ़ा। इस अभियान में माता व शिशु के पोषण के साथ स्वास्थ्य पर केंद्रण था। इस साल कोविड-19 फैलने के साथ केंद्रण तीन स्तंभों - हैल्थ, हाईज़ीन एवं पर्यावरण की ओर हो गया, जो मिलकर दुनिया को सुरक्षित रख सकते हैं।इस बारे में आरबी के सीईओ, लक्ष्मण नरसिम्हन ने कहा, "पिछले छः सालों से डेटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया ने 14 मिलियन भारतीयों के लिए बेहतर हाईज़ीन व सैनिटेशन प्रक्रियाओं के लिए व्यवहार में परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कोविड-19 ने हैल्थकेयर के ढांचे के विकास की ओर सरकार का ध्यान उत्पन्न किया है। यह स्पष्ट है कि कोरोना महामारी ने न केवल हैल्थ एवं हाईज़ीन के तरीके में परिवर्तन लाया है, अपितु सरकार, उद्योग एवं समाज द्वारा इसके दृष्टिकोण को भी बदल दिया है। सैल्फकेयर हैल्थ एवं हाईज़ीन विधियों को प्रोत्साहित करने के लिए हम भारतीयों के लिए हैल्दिली ऐप लॉन्च कर रहे हैं।" उन्होंने कहा, "हम 'ट्रेनिंग द ट्रेनर' के विचार के साथ एक सुरक्षित भविष्य के लिए आत्मनिर्भरता की विधियों का प्रसार कर रहे हैं। बेहतर डिजिटल टूल्स व टेक्नॉलॉजी द्वारा फ्रंटलाईन कर्मियों, टीचर्स एवं बच्चों को प्रिवेंटिव व प्राईमरी केयर में समर्थ बनाकर परिस्थितियों में परिवर्तन लाया जा सकता है। हमें इसके साथ ज्ञान का प्रसार भी करना होगा।"

भारत निर्यात बढ़ाने पर ध्यान दे, घरेलू बाजार को लेकर भ्रम से बचेः ए.सुब्रमणियम/चटर्जी

नयी दिल्ली। एजेंसी

पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमणियम ने पेंसिलवेनिया स्टेट यूनवर्सिटी के प्रोफेसर सुमित्रो चटर्जी के साथ लिखे एक शोध पत्र में सरकार की 'आत्मनिर्भर भारत' पहल की आलोचना करते हुए भारत को घरेलू बाजार को लेकर गुमराह करने वाले प्रलोभन से बचना चाहिए और पूरे जोश के साथ निर्यात को बढ़ावा देना चाहिए। यह कहा है। इसमें कहा गया है कि भारत आत्मकेंद्रित हो रहा है, घरेलू मांग को निर्यात से ज्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही है तथा व्यापार पाबंदियां बढ़ रही हैं। तीन दशक से जारी (वाह्य उदारीकरण की) प्रवृत्ति पलट रही है। 'इंडियाज इनवार्ड (री) टर्नः इज इट वारेंटेड? विल इट वर्क'(भारत का अंतर्मुखी मोड़ः किताना उचित) शीर्षक इस परचे में कहा गया है, "भारत को घरेलू बाजार को लेकर गुमराह करने वाले प्रलोभन से बचना चाहिए और पूरी शक्ति से निर्यात को बढ़ावा देना चाहिए।" इसमें कहा गया है कि निर्यातोन्मुख रुख में ढिलाई या उसे छोड़ना ठीक वैसा ही होगा जैसा कि सोने की अंडे देने वाली मुर्गी को मारना। "...वास्तव में आत्मनिर्भरता को अपनाना भारतीय अर्थव्यवस्था को औसत दर्जे की अर्थव्यवसा की ओर ले जाने का रास्ता है।" शोध पत्र के अनुसार आंतरिक बाजार की

ओर उन्मुख पर जोर कोविड-19 से पहले से उभर रहा था। यह आत्मनिर्भरता पर बढ़ते जोर के रूप में दिखाई दिया। इसमें कहा गया है कि यह बदलाव तीन गलत धारणा पर आधारित है... भारत एक बड़ा घरेलू बाजार है, भारत की वृद्धि घरेलू बाजार पर आधारित है न कि निर्यात पर और दुनिया वैश्वीकरण से दूर हो रही है, ऐसे में निर्यात की संभावना धुंधली है। पत्र के अनुसार भारत के पास अभी भी निर्यात का बड़ा अवसर है। खासकर कपड़ा और जूता-चप्पल जैसे श्रम गहन क्षेत्र में। लेकिन इन अवसरों को भुनाने के लिये अधिक खुलेपन तथा और वैश्विक एकीकरण की जरूरत है। इसमें कह गया है, "वास्तव में सार्वजनिक, कंपनियों तथा परिवार के स्तर पर बही-खातों पर दबाव को देखते हुए निर्यात उन्मुखता के रुख को त्यागना अंडे देने वाली मुर्गी को मारने जैसा होगा।" पत्र में कहा गया है कि भारत के वास्तविक बाजार को उपभोक्ता की निम्न क्रयशक्ति के आधार पर परिभाषित किया जाता है, जो बहुत बड़ा नहीं है। इसमें कहा गया है, "यह जीडीपी आंकड़ा से बहुत कम है। चीन की तुलना में बहुत कम है। विश्व बाजार का बहुत छोटा हिस्सा है। इसका कारण यह है कि भारत में गरीब ग्राहकों की संख्या अधिक है जबकि जो धनी हैं, वे अधिक खपत के बजाए बचत पर जोर देते हैं।"

दूरसंचार अन्य सभी क्षेत्रों के लिए मददगार, आवश्यक सेवा के रूप देखे सरकार : सीओएआई

नयी दिल्ली। एजेंसी

सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) ने कहा है कि अपनी बदलाव लाने की ताकत की वजह से दूरसंचार क्षेत्र अन्य क्षेत्रों को भी आगे बढ़ाने की क्षमता रखता है। दूरसंचार उद्योग के संगठन सीओएआई के महानिदेशक एस पी कोचर ने बुधवार को कहा कि सरकार को इस क्षेत्र को आवश्यक सेवा तथा उद्योगों के मददगार के रूप में देखना चाहिए, न कि राजस्व लाने वाले आकर्षक क्षेत्र के रूप में। उद्योग के शोध संस्थान ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम (बीआईएफ) द्वारा आयोजित एक वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कोचर ने कहा कि 5जी के साथ कृत्रिम मेधा (एआई), ऑगमेंटेड रीयल्टी, वर्चुअल रीयल्टी, रोबोटिक्स और भविष्य की अन्य प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। कोचर ने कहा, "यह क्षेत्र अन्य क्षेत्रों को सशक्त करेगा और अन्य सभी क्षेत्र इसकी बुनियाद पर आगे बढ़ेंगें।" उन्होंने कहा कि इस परिप्रेक्ष्य में दूरसंचार को 'अलग रूप' से देखा जाना चाहिए। सीओएआई के महानिदेशक ने कहा कि अभी सरकार दूरसंचार को राजस्व और कर की दृष्टि से एक आकर्षक क्षेत्र के रूप में देखती है। "लेकिन इसकी बदलती प्रकृति की वजह से उन्हें ज्यादा समय तक इसे इस रूप में नहीं देखना चाहिए।" कोचर ने कहा, "उन्हें दूरसंचार से जो राजस्व मिलता है, यदि हम इसे राजस्व का प्रमुख स्रोत मानें, लेकिन दूरसंचार की मदद से आगे बढ़ रहे उद्योगों से सरकार के राजस्व में वृद्धि हो रही है, मैं इसे द्वितीयक राजस्व कहूंगा। यह राजस्व सरकार को प्राप्त होने वाले प्रमुख या प्राथमिक राजस्व को पार कर जाएगा। " उन्होंने कहा, "ऐसे में उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वे इस क्षेत्र को पानी और बिजली की तरह आवश्यक सेवाओं के रूप में देखें। ऐसे में इसे तेजतर्रार बनाया जाना चाहिए और ग्राहकों को सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित होनी चाहिए।" ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम द्वारा 'डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशनः पाथ टू एक्जाबाइट एरा' पर वर्चुअल डायलॉग को संबोधित करते हुए कोचर ने कहा कि नई प्रौद्योगिकियों और 5जी से लोगों के काम करने का तरीका बदल जाएगा। ऐसे में लोगों को नए सिरे से कुशल बनाने और प्रशिक्षण देने की जरूरत होगी। इसी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आदित्य बिड़ला फैशन एंड रिटेल (एबीएफआरएल) के वाइस चेयरमैन हिमांशु कपानिया ने कहा कि डिजिटल बदलाव तय है। उन्होंने कहा कि डेटा एक मूल्यवान संपत्ति है, जिसका अभी दोहन नहीं हो पाया है। निजता और सुरक्षा की चुनौतियों से निपटते हुए इसकी पहुंच बढ़ाई जानी चाहिए।

EPFO: ईपीएफओ ने शुरू की व्हाट्सऐप हेल्पलाइन सेवा, जानिए क्या है नंबर- यहां कर सकते हैं शिकायत

नई दिल्ली। एजेंसी

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने अंशधारकों की शिकायतों के त्वरित समाधान को लेकर व्हाट्सऐप हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह सुविधा ईपीएफओ के शिकायतों के समाधान के लिए अन्य मंचों के अलावा है। इन मंचों में ईपीएफआईजीएमएस पोर्टल (ईपीएफओ के ऑनलाइन शिकायत समाधान पोर्टल), सीपीजीआरएएमएस, सोशल मीडिया मंच (फेसबुक और ट्विटर) और 24 घंटे काम करने वाला कॉल सेंटर शामिल हैं। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ईपीएफओ ने अपने सदस्यों के जीवन को और ज्यादा सुगम बनाने के लिए व्हाट्सऐप आधारित हेल्पलाइन-सह-शिकायत निवारण प्रणाली की शुरुआत की है। निर्बाध पहल की श्रृंखला के अंतर्गत उठाये गये इस कदम का मकसद अंशधारकों को कोविड-19 महामारी के दौरान निर्बाध और बिना व्यवधान के सेवाओं डिलिवरी सुनिश्चित करना है। इस पहल के माध्यम से पीएफ अंशधारक व्यक्तिगत स्तर पर ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ सीधे बातचीत कर सकते हैं। अब ईपीएफओ के सभी 138 क्षेत्रीय कार्यालयों में व्हाट्सऐप हेल्पलाइन सेवाएं शुरू हो चुकी है। कोई भी संबंधित पक्ष जहां पर उनका पीएफ खाता है, उस संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सऐप

संदेश के माध्यम से, ईपीएफओ से जुड़ी सेवाओं को लेकर किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज कर सकता है। सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के व्हाट्सऐप हेल्पलाइन नंबर ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। क्षेत्रीय कार्यालयों के व्हाट्सऐप हेल्पलाइन नंबर ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर मिल जाएंगे।

कोविड के दौर में खूब फला-फूला ड्राईफ्रूट्स और नट्स का बाजार

नई दिल्ली। एजेंसी

वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौर में जहां एक ओर तमाम बिजनेस मंदी का शिकार है, वहीं ड्राई फ्रूट्स और नट्स (Dry fruits & Nuts) का कारोबार खूब फल फूल रहा है। लॉकडाउन के शुरुआती 10-15 दिन छोड़ दें, तो बाजार में ड्राईफ्रूट्स की जबरदस्त डिमांड देखी गई है। इसकी बड़ी वजह है कि लोगों ने ड्राईफ्रूट्स को इम्युनिटी बूस्टर के तौर पर लिया है। लिहाजा, इसकी मांग में काफी इजाफा हुआ है।

ई कामर्स पर खूब बिके ड्राईफ्रूट्स

इंटरनेशनल फ्रूट्स एंड नट्स ऑर्गनाइजेशन के ड्राईफ्रूट्स कंसल्टेंट रवींद्र मेहता का कहना है कि लोगों ने घर पर बैठकर हेल्दी नट्स पर खूब पैसा खर्च किया है। घर में लोगों ने तरह-तरह के पकवान और मिठाइयां बनाईं, जिसमें सूखे मेवों की जरूरत पड़ी। इसका दूसरा लाभ ई-कॉमर्स कंपनियों को हुआ है, जिन्होंने घर-घर ड्राईफ्रूट्स सप्लाई किए हैं। कारोबार बिजनेस टू कस्टमर तक चला गया। होलसेलर की जहां महीनेभर में 10 करोड़ रुपए की सेल होती थी, वह 30 करोड़ रुपए पहुंच गई है। सबसे ज्यादा बादाम की बिक्री हुई, उसके बाद अंजीर, अखरोट गिरी और मुनक्कों की सेल हुई। काजू की डिमांड में ज्यादा बढ़ोत्तरी नहीं हुई, क्योंकि इसका अधिक इस्तेमाल हलवाई करते हैं। हालांकि, ब्रांडेड नमकीन कंपनियों ने जरूर काजू का इस्तेमाल किया।

दामों में आई काफी गिरावट

एक्सपर्ट की माने तो पिछले सालों के मुकाबले 2020 में ड्राईफ्रूट्स के दामों में 40 प्रतिशत तक गिरावट आई। बादाम का रेट 2 डॉलर 25 सेंट प्रति पाउंड से गिरकर 1 डॉलर 40 सेंट तक आ गया। कारोबारियों ने भी 20 प्रतिशत तक मुनाफा कमया है। अमेरिका में बादाम की फसल अगस्त में तैयार होती है, जो इस साल काफी अच्छी हुई है। इसकी पहली खेप सितंबर तक हिन्दुस्तान पहुंच जाती थी, लेकिन कोविड की वजह से इस बार कुछ लेट हुआ है।

रक्षा बंधन के बाद सेल में इजाफा

ट्रेडर्स के मुताबिक, रक्षा बंधन 3 अगस्त के बाद से ड्राईफ्रूट्स की डिमांड में और बढ़ोत्तरी दर्ज हुई। क्योंकि यह पहला त्योहार रहा, जिसमें बहन अपने भाइयों से मिलने गईं। इसमें दोनों परिवारों को मालूम था कि वहां कोरोना का खतरा नहीं है। अगस्त से पहले तक तो लोगों में कोरोना को लेकर ज्यादा ही डर था। बाद में मिठाइयों की सेल भी उठनी शुरू हुई। अब हलवाइयों को भी उम्मीद है कि दीपावली में 50 से 60 प्रतिशत तक काम कर लेंगे। यही वजह है कि उन्होंने भी ड्राईफ्रूट्स की बुकिंग करानी शुरू कर दी है।

कॉरपोरेट गिफ्टिंग पर असर

इस बार कॉरपोरेट गिफ्टिंग पर बुरा असर पड़ने की आशंका है। कोरोना की वजह से बहुत सी कंपनियां बंद हो गई हैं, तमाम कंपनियों में कर्मचारियों की संख्या घट गई है। महामारी की वजह से बिजनेस मंदा हो गया है। कुछ ही कंपनियां दीपावली के अवसर पर अपने एम्पलॉय को गिफ्ट देंगी। उनका अनुमान है कि इस वजह से इसका करीब 30 प्रतिशत नुकसान झेलना होगा।

3 लाख टन तक बादाम के आयात का अनुमान

बादाम कारोबारी अप्रेश गर्ग का कहना है कि देश में लॉकडाउन लगते ही कुछ समय तक ड्राईफ्रूट्स का कारोबार भी ठप हुआ है। बाद में प्रचार हुआ कि ड्राई फ्रूट्स खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है। सोशल मीडिया पर काफी लाभ बताए गए। इसके बाद मार्केट में डिमांड आनी शुरू हुई। सबसे ज्यादा मांग बादाम और अखरोट की रही। दूसरा इस साल अमेरिका में फसल भी अच्छी हुई है। पिछले 4 महीने में 30-40 प्रतिशत तक बादाम और अखरोट की सेल बढ़ी है। भारत में अब तक सालाना करीब 2 लाख 10 हजार टन बादाम का आयात होता था, जो इस बार बढ़कर 3 लाख टन तक जाने का अनुमान है। अमेरिका में नई फसल निकल गई है, जो करीब महीनेभर में भारत आयात हो जाएगी। इसके बाद थोक कारोबारी भी माल का ऑर्डर बुक करेंगे। इस साल त्योहारी सीजन और सर्दी साथ-साथ आ रही है। इसका असर भी सेल पर पड़ेगा। शादियों का सीजन कारोबार के लिहाज से संशय में है कि समारोह में कितने मेहमानों को अनुमति मिलेगी? उसी के आधार पर खाने-पीने के आइटम बनते हैं।

दीपावली पर मिठाइयों का 50 प्रतिशत काम

फेडरेशन ऑफ स्वीट्स एंड नमकीन मैन्यफैक्चरर्स के प्रेसिडेंट वीरेंद्र जैन का कहना है कि कोविड के दौर में मिठाई की सेल पर असर पड़ना तय है। मिठाई के बाद लेन-देन में ड्राईफ्रूट्स या चॉकलेट का नंबर आता है। अभी ड्राईफ्रूट्स को ज्यादा सेफ माना जा रहा है। इससे इम्युनिटी भी स्ट्रॉन्ग होती है। इस साल मिठाई पर लोगों का कम फोकस रहने वाला है। पिछले सालों की तुलना में इस बार दीपावली पर 50 प्रतिशत काम मानकर चल रहे हैं। आज कल भी औसत सेल 50 प्रतिशत से कम है। अब शादी-ब्याह, खुशी या फंक्शन्स में ड्राईफ्रूट्स खिलाकर मुंह तो मीठा नहीं कर सकते, उसके लिए मिठाई ही जरूरी है। पहले जहां लोग 4 डिब्बे खरीदते थे, इस बार कम खरीदेंगे। कोरोना काल में आने-जाने पर फर्क पड़ा है, जिसका असर लेन-देन पर भी रहेगा। कॉरपोरेट कंपनियों के ऑर्डर भी पिछले सालों के मुकाबले कम आएंगे। क्योंकि महामारी के दौर में हर कोई नुकसान में हैं। कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया है, जिसका असर ऑर्डर पर पड़ेगा। अभी फेस्टिवल को लेकर उत्साह नहीं है। लोगों का हॉस्पिटल खर्च बढ़ा है।

कोरोना कवच पॉलिसी को लेकर बड़ी खबर

IRDAI का आदेश रिन्यूअल के लिए ना कराएं इंतजार

नई दिल्ली। एजेंसी

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने बीमा कंपनियों से कोरोना कवच या कोरोना रक्षक पॉलिसियों के नवीनीकरण (रिन्यूअल) पर बीमित व्यक्ति को लेकर 15 दिन की प्रतीक्षावधि (वेटिंग पीरियड) नहीं लगाने के लिए कहा है। IRDAI ने एक परिपत्र में कहा कि ग्राहकों को किसी भी अवधि की कोरोना कवच और कोरोना रक्षक पॉलिसियों का नवीनीकरण साढ़े तीन माह, साढ़े छह माह और साढ़े नौ माह की अवधि में कराने का विकल्प मिलना चाहिए।

15 दिनों का वेटिंग पीरियड समाप्त हो

हालांकि पॉलिसी धारक को पॉलिसी का नवीनीकरण मौजूदा पॉलिसी के समाप्त होने से पहले कराना होगा। ईईईई ने कहा कि पॉलिसी के नवीनीकरण में अतिरिक्त 15 दिन की प्रतीक्षावधि नहीं लगाई जानी चाहिए और पॉलिसी का लाभ लगातार जारी रहना चाहिए। इन पॉलिसियों का नवीनीकरण 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए करने की अनुमति है। उल्लेखनीय है कि बीमा कंपनियों ने लघु अवधि की कोरोना कवच और कोरोना रक्षक पॉलिसियां जारी की थीं। यह पॉलिसियां साढ़े तीन महीने, साढ़े छह महीने या साढ़े नौ महीने की अवधि के लिए जारी की थीं।

रिन्यूअल, ट्रांसफर का ऑप्शन दें बीमा कंपनियां

इन पॉलिसियों को कोरोना वायरस के इलाज पर होने वाले व्यय पर बीमा सुरक्षा देने के लिए तैयार किया गया था। ईईईई ने एक परिपत्र में कहा कि बीमा कंपनियां ग्राहकों को पॉलिसी के नवीनीकरण, स्थानांतरण और पोर्टिबिलिटी का विकल्प भी देना चाहिए।

महामारी से प्रभावित समुदायों के लिए

प्रत्यक्ष नगद सहायता वाली मांग को मिला 15 लाख लोगों का समर्थन

नयी दिल्ली। एजेंसी

23 राज्यों के सीएसओ नेटवर्क के सहयोग से तमिलनाडु एलायंस द्वारा की जा रही मांग को केवल 20 दिनों में 15 लाख लोगों का समर्थन हासिल हो चुका है। इसमें लॉकडाउन से प्रभावित परिवारों के लिए 6000 रुपए प्रति माह प्रत्यक्ष नकद सहायता उपलब्धा कराने की मांग की गई है। इस मांग में सरकार से संगठित क्षेत्र के श्रमिकों और अन्य कमजोर समुदायों की आर्थिक स्थिति पर लॉकडाउन के प्रभाव को कम करने और उन्हेंम भुखमरी, जोखिमपूर्ण उधार लेने, मानव तस्कीरी, बंधुआ मजदूरी और बाल मजदूरी से बचाने के लिए चार माह तक प्रति माह 6000 रुपए की सहायता उपलब्धत कराने का आग्रह किया गया है। कोविड-19 महामारी एक वैश्विक स्वास्थ संकट है, जिसने पूरी दुनिया में 35,216,168 लाख लोगों को संक्रमित किया है और 1,037,340 लोगों की जान ली है। महामारी को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए राष्ट्राव्यापी लॉकडाउन की वजह से अप्रैल से जुलाई के दौरान 189 लाख लोग बेरोजगार हुए। इनमें 70 प्रतिशत से अधिक लोग दैनिक वेतनभोगी, हॉकर्स और छोटे व्योपारी थे और उन्हें जीवित रहने के लिए अपनी सीमित बचत का मजबूरन उपयोग करना पड़ा। अचानक लॉकडाउन से एक गंभीर प्रवासी संकट पैदा हुआ, जहां लाखों प्रवासी श्रमिकों को अचानक काम और आय से हाथ धोना पड़ा। सरकारी ग्रामीण रोजगार योजना महात्मा गांधी राष्ट्री य ग्रामीण रोजगार योजना (मनरेगा) के मुताबिक, पिछले महीने इसके तहत 2.42 करोड़ ग्रामीण परिवारों ने काम के लिए आवेदन

किया, जो पिछले साल अगस्तग की तुलना में 66 प्रतिशत अधिक है।

एक सर्वे के मुताबिक, ऐसा अनुमान है कि 25 प्रतिशत से अधिक प्रवासी जुलाई के अंत तक गांवों में काम की तलाश कर रहे थे। लॉकडाउन और प्रवासियों पर इसके प्रभाव के कारण, आगे आने वाले महीनों में, बच्चे एक गंभीर संकट में होंगे और परिवार का खर्च पूरा करने के लिए उन्हें काम करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आर्थिक गतिविधियों के दोबारा शुरू होने के साथ, यहां इस बात का जोखिम है कि वापस लौटने वाले प्रवासी बच्चों को अपने साथ शहर लेकर आएं या फिर बच्चों को तस्कारों के साथ जाने दें। याचिका का उदेश्यो कोविड-19 संकट से कमजोर लोगों की रक्षा करना और उन्हें सुरक्षा प्रदान करना है। ऐसे समय में, सरकार के लिए यह जरूरी है कि वह अपने जरूरतमंद नागरिकों को भोजन और नकद दोनों रूप में प्रत्यिक्ष मदद उपलब्ध कराए। पीडीएस के तहत नवंबर तक राशन कार्ड वाले लोगों को मदद दी जाएगी, लेकिन इसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए। हालांकि, राशन के साथ-साथ उन लोगों को नकद भी उपलब्धद कराना जरूरी है, जो रोजगार खो चुके हैं और उनके पास आय का कोई जरिया नहीं है।

मांग पर बोलते हुए, टीएनए के डा. पी. बालामुरुगन ने कहा, 'भारत को अपने कमजोर लोगों को बचाने की जरूरत है और हम सरकार से तत्काहल चार महीनों के लिए 6000 रुपए प्रति माह नकद सहायता उपलब्धत कराने की मांग कर रहे हैं। यह सहायता गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले कमजोर परिवारों के लिए नकदी उपलब्ध कराएगी। पिछले कुछ हफ्तों में हमने साथ मिलकर प्रभावित परिवारों के प्रति एकजुटता का प्रदर्शन करने के लिए समर्थन हासिल किया है और हमें पूरी उम्मी द है कि इसे वास्त विकता में बदलने के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा हमारी इस मांग को जरूर मंजूर किया जाएगा। पूरे देशभर से प्राप्तत हुई प्रतिक्रिया की रफ्तार से हम काफी चकित हैं- हताश परिस्थितियों में लोग चाहते हैं कि उनकी जरूरतों पर ध्यान दिया जाए।'

नवरात्रि में क्यों करते हैं कलश स्थापना

हिंदू धर्म में पूजा-पाठ और किसी धार्मिक अनुष्ठान में कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में कलश को सुख-समृद्धि,ऐश्वर्य और मंगल कामनाओं का प्रतीक माना गया है। बिना कलश स्थापना के कोई भी धार्मिक अनुष्ठान पूरा नहीं माना जाता है। हर वर्ष अश्विन माह के नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा तिथि पर कलश स्थापना की जाती है। इसलिए नवरात्रि पर मां दुर्गा की पूजा करते समय माता की प्रतिमा के सामने कलश की स्थापना करनी चाहिए।

वरुण और अग्नि को साक्षात देवता माना जाता है। वरुण का प्रतीक कुंभ है। कुंभ को देखते ही समुद्र मंथन की कथा का स्मरण होता है। घट के साथ ही जुड़ी है श्रीकृष्ण की बाल लीला और समुद्र मंथन का प्रसंग।

मोहिनी अवतार के हाथों देव-असुरों के बीच अमृत बांटने की कथा स्मरण हो आती है। शास्त्रों में कलश दर्शन को देव दर्शन के समकक्ष माना गया है। कलश स्थापना के समय जिन श्लोकों का उच्चारण और जो भावना व्यक्त की जाती है, उसी से स्पष्ट हो जाता है कि कलश क्यों मंगलसूचक है।

कलश की स्थापना और उसके पूजन के समय पुजारी शास्त्रसम्मत कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हैं।

कलश पूजा का महत्व

कलशस्य मुखे विष्णु : कंठे रुद्रः समाश्रित।
मूल तस्य, स्थित ब्रह्मा मध्ये मातगणः समाश्रितः।।
भ्रातः कान्चलेपगोपितबहिस्ताम्राकृते सर्वतो।
मा भैषीः कलशः स्थिरो भव चिरं देवालयस्योपरि।।
ताम्रत्वं गतमेव कांचनमयी कीर्तिः स्थिरा ते धुना।
नान्स्तत्त्वविचारणप्रणयिनो लोका बहिबरुद्धयः।।

कांचन से कीर्ति महान है और सुवर्ण से सुनहरा जीवन श्रेष्ठ है। मंदिर के शिखर पर स्थित कलश वह कीर्ति और वैसा जीवन प्राप्त कर चुका है। अब उसे अपने बारे में हीनभाव रखने का कोई कारण नहीं है। छोटा मानव भी महान कार्य में निमित्त बना हो तो वह जीवन में महानता के शिखरों को प्राप्त कर सकता है। उसके बाद उसे छोटेपन का अनुभव नहीं करना चाहिए। कलश भारतीय संस्कृति का अग्रगण्य प्रतीक है इसलिए तो महत्वपूर्ण सभी शुभ प्रसंगों में पुण्याहवाचन कलश की साक्षी में तथा सान्निध्य में होता है।प्रत्येक शुभ प्रसंग या कार्य के आरंभ में जिस तरह विघ्नहर्ता गणपति जी की पूजा की जाती है उसी तरह कलश की भी पूजा होती है। देवपूजा के स्थान पर इस कलश को अग्रस्थान प्राप्त होता है। पहले इसका पूजन, फिर इसे नमस्कार और बाद में विघ्नहर्ता गणपति को नमस्कार! ऐसा प्राधान्यप्राप्त कलश और उसके पूजन के पीछे अति सुंदर भाव छिपा हुआ है।

नवरात्रि के शुभ पर्व में कलश पर स्वस्तिक चिह्न अंकित करते ही सूर्य आकर उस पर आसनस्थ होते हैं कलश को सजाते ही वरुणदेव उसमें विराजमान होते हैं। जो संबंध कमल-सूर्य का है वही संबंध कलश वरुण का है। वास्तव में कलश यानी लोटे में भरा हुआ या घड़े में भरा हुआ साधारण जल। परंतु कलश की स्थापना के बाद उसके पूजन के बाद वह जल सामान्य जल न रहकर दिव्य ओजस्वी बन जाता है।

तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदाशास्ते यजमानो हविर्भिः।
अहेळमानो वरुणोहबोध्यु रुशंसा मा न आयुः प्रमोषीः।।

हे वरुणदेव! तुम्हें नमस्कार करके मैं तुम्हारे पास आता हूं। यज्ञ में आहुति देने वाले की याचना करता हूं कि तुम हम पर नाराज मत होना। हमारी उम्र कम नहीं करना आदि वैदिक दिव्य मंत्रों से भगवान वरुण का

जानिए कलश का शुभ महत्व

आवाहन करके उनकी प्रस्थापना की जाती है और उस दिव्य जल का अंग पर अभिषेक करके रक्षा के लिए प्रार्थना की जाती है। कलश पूजन की प्रार्थना के श्लोक भी भावपूर्ण हैं। उसकी प्रार्थना के बाद वह कलश केवल कलश नहीं रहता, किंतु उसमें पिंड ब्रह्मांड की व्यापकता समाहित हो जाती है।

कलशस्य मुखे विष्णुः कंठे रुद्रः समाश्रितः।
मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्मृताः।।
कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुंधरा।
ऋग्वेदोअथ यजुर्वेदः सामवेदो ह्यथवर्णः।।
अंगैच्श सहिताः सर्वे कलशं तु समाश्रिताः।
अत्र गायत्री सावित्री शांतिपृष्टिकरी तथा।
आयांतु मम शांत्यर्थ्य दुरितक्षयकारकाः।।
सर्वे समुद्राः सरितस्तीर्थानि जलदा नदाः।
आयांतु मम शांत्यर्थ्य दुरितक्षयकारकाः।।

हमारे ऋषियों ने छोटे से पानी के लोटे में सभी देवता, वेद, समुद्र, नदियां, गायत्री, सावित्री आदि की स्थापना कर पापक्षय और शांति की भावना से सभी को एक ही प्रतीक में लाकर जीवन में समन्वय साधा है। बिंदु में सिंधु के दर्शन कराए हैं। नए घर में प्रवेश करने से पहले कुंभ रखने की प्रथा प्रचलित है। जलपूर्ण कुंभ की तरह घर भावपूर्ण और नवपल्लवित रहे, ऐसी मंगलकामना इसके पीछे रही है। कलश या कुंभ पर श्रीफल रखने से उसकी शोभा दोगुनी होती है। श्रेष्ठागमन के समय माथे पर श्रीफलयुक्त कलश लेकर खड़ी रहने वाली कुमारिकाओं को हम कई बार देखते हैं। भावभीने आतिथ्य सत्कार का यह अनोखा प्रकार है। गुजरात में नवरात्रि के प्रसंग पर खेला जाने वाला गरबा कलश या कुंभ का ही स्वरूप है। गरबा सजल होने के बजाय सतेज होता है। वास्तु और स्थापत्य शास्त्र में भी कलश का सबसे खास महत्व है। देवी दुर्गा की पूजा में कलश क्यों स्थापित करते हैं ? कलश स्थापना से संबंधित हमारे पुराणों में एक मान्यता है, जिसमें कलश को भगवान विष्णु का रुप माना गया है। इसलिए लोग देवी की पूजा से पहले कलश का पूजन करते हैं। पूजा स्थान पर कलश की स्थापना करने से पहले उस जगह को गंगा जल से शुद्ध किया जाता है और फिर पूजा में सभी देवी-देवताओं को आमंत्रित किया जाता है। कलश को पांच तरह के पत्तों से सजाया जाता है और उसमें हल्दी की गांठ, सुपारी, दूर्वा, आदि रखी जाती है। कलश को स्थापित करने के लिए उसके नीचे बालू की वेदी बनाई जाती है और उसमें जौ बोये जाते हैं। जौ बोने की परंपरा धन-धान्य देने वाली देवी अन्नपूर्णा को खुश करने के लिए की जाती है। मां दुर्गा की फोटो या मूर्ति को पूजा स्थल के बीचों-बीच स्थापित करते हैं और मां का श्रृंगार रोली ,चावल, सिंदूर, माला, फूल, चुनरी, साड़ी, आभूषण और सुहाग से करते हैं। पूजा स्थल में एक अखंड दीप जलाया जाता है जिसे व्रत के आखिरी दिन तक जलाया जाना चाहिए। कलश स्थापना करने के बाद, गणेश जी और मां दुर्गा की आरती करते है जिसके बाद नौ दिनों का व्रत शुरू हो जाता है। माता में श्रद्धा और मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए बहुत-से लोग पूरे नौ दिन तक उपवास भी रखते हैं। नवमी के दिन नौ कन्याओं को जिन्हें माँ दुर्गा के नौ स्वरूपों के समान माना जाता है, श्रद्धा से भोजन कराई जाती है और दक्षिणा आदि दी जाती है। भक्त नौ दिनों तक देवी की पूजा और उपवास करते हैं और दसवें दिन कन्या पूजन करने के पश्चात् उपवास खोलते हैं।

कलश स्थापना क्यों की जाती है?

कलश विश्व ब्रह्मांड का, विराट ब्रह्म का, भू-पिंड (ग्लोब) का प्रतीक है। इसे शांति और सृजन का संदेशवाहक कहा जाता है। संपूर्ण देवता कलशरूपी पिंड या ब्रह्मांड में व्यष्टि या समष्टि में एकसाथ समाए हुए हैं। वे एक हैं तथा एक ही शक्ति से सुसंबंधित हैं। बहुदेववाद वस्तुतः एक देववाद का ही एक रूप है। एक माध्यम में, एक ही केंद्र में समस्त देवताओं को देखने के लिए कलश की स्थापना की जाती है। कलश को सभी देव शक्तियों, तीर्थों आदि का संयुक्त प्रतीक मानकर उसे स्थापित एवं पूजित किया जाता है। वेदोक्त मंत्र के अनुसार कलश के मुख में विष्णु का निवास है, उसके कंठ में रुद्र तथा मूल में ब्रह्मा स्थित हैं।

कलश के मध्य में सभी मातृशक्तियां निवास करती हैं। कलश में समस्त सागर, सप्तद्वीपों सहित पृथ्वी, गायत्री, सावित्री, शांतिकारक तत्व, चारों वेद, सभी देव, आदित्य देव, विश्वदेव, सभी पितृदेव एकसाथ निवास करते हैं। कलश की पूजा मात्र से एकसाथ सभी प्रसन्न होकर यज्ञ कर्म को सुचारुरूपेण संचालित करने की शक्ति प्रदान करते हैं और निर्विघ्नतया यज्ञ कर्म को समाप्त करवाकर प्रसन्नतापूर्वक आशीर्वाद देते हैं। कलश में पवित्र जल भरा रहता है। इसका मूल भाव यह है कि हमारा मन भी जल की तरह शीतल, स्वच्छ एवं निर्मल बना रहे। हमारे शरीररूपी पात्र हमेशा श्रद्धा, संवेदना, तरलता एवं सरलता से लबालब भरे रहें। इसमें क्रोध, मोह, ईर्ष्या, घृणा आदि की कुत्सित भावनाएं पनपने न पाएं। अगर पनपें भी तो जल की शीतलता से शांत होकर घुलकर निकल जाएं। कलश के ऊपर आम्रपत्र होता है जिसके ऊपर मिट्टी के पात्र में केसर से रंगा हुआ अक्षत (चावल) रहता है जिसका भाव यह होता है कि परमात्मा यहां अवतरित होकर हम अक्षत अथवा अविनाशी आत्माओं एवं पंचतत्व की प्रकृति को शुद्ध करें। दिव्यज्ञान को धारण करने वाली आत्मा आम्रपत्र (पल्लव) के समान हमेशा हरियाली (सुखमय) युक्त रहे। कलश में डाला जाने वाला दूर्वा-कुश, सुपारी, पुष्प इस भावना को दर्शाती है कि हमारी पात्रता में दूर्वा (दूब) के समान जीवनी-शक्ति, कुश जैसी प्रखरता, सुपारी के समान गुणयुक्त स्थिरता, फूल जैसा उल्लास एवं द्रव्य के समान सर्वग्राही गुण समाहित हो जाए।

नवरात्रि पर जवारे क्यों उगाए जाते हैं

नवरात्रि पर ज्वारे उगाए जाते हैं। घट स्थापना के ही दिन माता की चौकी के सामने जवारे बोए जाते हैं। मान्यता है नवरात्रि पर जौ बोना बहुत ही शुभ होता है।

■कलश के सामने मिट्टी के पात्र में जौ को बोया जाता है। नवरात्रि में जौ इसलिए बोया जाता है क्योंकि सृष्टि की शुरुआत में जौ ही सबसे पहली फसल थी। जौ उगने या न उगने को भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान के तौर पर देखा जाता है। ■अगर जौ तेज़ी से बढ़ते हैं तो घर में सुख-समृद्धि आती है। जवारे जिन घरों में तेजी से बढ़ते हैं तो मां दुर्गा के आशीर्वाद से उनके घरों में खुशियां और समृद्धि भी उतनी ही तेजी से आती हैं। ■अगर ये बढ़ते नहीं और मुरझाए हुए रहते हैं तो भविष्य में किसी तरह के अनिष्ट का संकेत देते हैं।■ पीले और सामान्य जौ आने पर उस वर्ष जीवन भी साधारण रहेगा ऐसा माना जाता है।

नवरात्रि पर मात्र 5 रुपए में प्रसन्न होंगी देवी ले आइए ये 10 सामग्री

नवरात्रि पर आप माता रानी को बहुत सरल और सस्ते उपायों से खुश कर सकते हैं। जानिए वे सस्ते उपाय क्या हैं? पढ़ें सरल उपाय...

पान :- ताजे नए पान लाकर उस पर एक रुपए का सिक्का रखकर मां भवानी के सामने रखें।
सुपारी :- 5 रुपए की पूजा सुपारी लाकर देवी मां को समर्पित करें तो भी वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देंगी।
रुई :- 5 रुपए की रुई खरीद कर उसे माता रानी को अर्पित करें तो वह उतनी ही प्रसन्न होंगी जितनी मंहगे पौराणिक उपायों से होती है।
गुड़ :- अगर आप महंगे प्रसाद / भोग माताजी को नहीं चढ़ा सकते तो 5 रुपए का गुड़ लाकर पूरे भक्ति भाव से देवी के समक्ष रखें। आपको शुभ आशीर्वाद अवश्य मिलेंगे।
काले उबले चने :- देवी मां को प्रसन्न करने का यह भी बहुत सरल और सस्ता उपाय है। 5 रुपए के काले उबले चने भी अंबे मां को प्रसन्न करेंगे।
मिश्री : यह मीठा भोग मां प्रेम से ग्रहण करती हैं।
ध्वजा : नवरात्रि में लाल वस्त्र की छोटी सी ध्वजा चढ़ाकर मां को प्रसन्न किया जा सकता है।
मेहंदी-कुमकुम : मेहंदी के छोटे पैकेट थोड़े से कुमकुम के साथ रखने से भी मां का आशीष मिलता है।
लौंग-इलायची : 5 रुपए की लौंग और इलायची अर्पित करने से भी माता रानी खुश हो जाती हैं।
दूध और शहद : छोटी सी कटोरी में जरा सा दूध और बूंद भर शहद भी मां को प्रसन्न करता है।

नवरात्रि 2020 में लग्नानुसार जपें मां दुर्गा का बस एक मंत्र,कष्टों का होगा अंत

नवरात्रि के शुभ अवसर पर राशि के अतिरिक्त लग्न के अनुसार भी दुर्गा मंत्र पढ़े जाते हैं। आइए जानें क्या है आपका शुभ मंत्र...

मेष लग्न- ॐ विंध्यवासिनी नमः।
वृषभ लग्न- ॐ महाविद्या नमः।
मिथुन लग्न- ॐ त्रिपुरा नमः।
कर्क लग्न- ॐ सुगोत्रा नमः।
सिंह लग्न- ॐ मृडानी नमः।
कन्या लग्न- ॐ सुखदिता नमः।
तुला लग्न- ॐ कोपना-कृति नमः।
वृश्चिक लग्न- ॐ स्वर्ग-गति नमः।
धनु लग्न- ॐ भवप्रीता नमः।
मकर लग्न- ॐ पुरवासिनी नमः।
कुंभ लग्न- ॐ वसुधाकारा नमः।
मीन लग्न- ॐ शुभा नमः।

लग्न अनुसार देवी आराधना मंत्र का 9 दिनों तक निरंतर पाठ करने से समस्त मनोरथ पूर्ण होंगे। शारीरिक कष्ट व मानसिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी।

सब्जियों के बढ़ते दाम से सितंबर में थोक मुद्रास्फीति सात महीने के उच्चतम स्तर पर

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

खाद्य वस्तुओं विशेषकर सब्जियों की कीमतों में तेजी के चलते थोक कीमतों पर आधारित मुद्रास्फीति (डब्ल्यूपीआई) सितंबर 2020 में बढ़कर 1.32 प्रतिशत हो गयी। यह डब्ल्यूपीआई का सात महीने का उच्चतम स्तर है और मुद्रास्फीति के दबाव में रिजर्व बैंक के लिए नीतिगत ब्याजदर में नरमी करने की संभावना और धूमिल लगती है। थोक कीमतों पर आधारित मुद्रास्फीति अगस्त में 0.16 प्रतिशत थी। बुधवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, ''मासिक डब्ल्यूपीआई (थोक मूल्य सूचकांक) पर आधारित मुद्रास्फीति की वार्षिक दर सितंबर में 1.32 प्रतिशत (अनंतिम) रही, जो पिछले साल की समान अवधि में 0.33 प्रतिशत थी।'' थोक मुद्रास्फीति में भी खुदरा मुद्रास्फीति के साथ-साथ ही बढ़ रही है। खुदरा मुद्रास्फीति सितंबर महीने में बढ़कर आठ महीने के उच्चतम स्तर 7.34 प्रतिशत पर पहुंच गयी है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इक्रा की प्रधान अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा, रिजर्व बैंक नीतिगत दर तय करते समय भले ही खुदरा मुद्रास्फीति पर गौर करता है, लेकिन थोक मुद्रास्फीति पर आज के आंकड़े से इस बात की

संभावना और प्रबल दिखती है कि केंद्रीय बैंक नीतिगत ब्याज दर पर अभी और अधिक समय तक यथास्थिति बरकरार रखेगा। अगस्त से पहले डब्ल्यूपीआई पर आधारित मुद्रास्फीति लगातार चार महीनों शूरू से नीचे (अप्रैल में नकारात्मक 1.57 प्रतिशत, मई में नकारात्मक 3.37 प्रतिशत, जून में नकारात्मक 1.81 प्रतिशत और जुलाई में नकारात्मक 0.58 प्रतिशत) थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार खाद्य वस्तुओं की महंगाई 8.17 प्रतिशत रही, जबकि अगस्त में यह 3.84 प्रतिशत थी। समीक्षाधीन अवधि में अनाज की कीमतों में गिरावट आयी, जबकि दालें महंगी हुईं। इस दौरान सब्जियों के महंगा होने की दर 36.54 प्रतिशत के उच्च स्तर पर थी।

आलू की कीमत एक साल पहले के मुकाबले 107.63 प्रतिशत अधिक थी, हालांकि प्याज की कीमतों में 31.64 प्रतिशत गिरावट देखने को मिली। फलों के दाम भी 3.89 प्रतिशत कम हुए। आलोच्य महीने के दौरान अनाज की कीमतों में 3.91 प्रतिशत की गिरावट आयी। दालों के दाम में 12.53 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सरकारी आंकड़ों में कहा गया है कि इस दौरान विनिर्मित उत्पाद श्रेणी में महंगाई दर बढ़कर 1.61 फीसदी हो गयी। अन्य श्रेणियों में 'ईंधन और बिजली' की कीमतों में 9.54 प्रतिशत गिरावट देखी गयी। इस श्रेणी में इस वित्त वर्ष की शुरुआत से लगातार कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। इसी तरह गैर-खाद्य श्रेणी में 0.08 प्रतिशत की अपस्फीति देखी गयी। बंधन बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री एवं अनुसंधान प्रमुख सिद्धार्थ सान्याल ने कहा खुदरा और थोक मुद्रास्फीति के बीच छह प्रतिशत से अधिक का अंतर यह बताता है कि खुदरा दाम आपूर्ति श्रृंखला के अवरोधों के कारण बढ़ रहे हैं, न कि मांग के कारण। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के अर्थशास्त्री सुनील कुमार सिन्हा ने कहा कि थोक मुद्रास्फीति कम आधार प्रभाव के कारण आगे और बढ़ सकती है। इसके नवंबर तक बढ़ने की उम्मीद है।

भारत की पहली ऑटोनोमस (लेवल1) प्रीमियम एसयीवी- MG GLOSTER लॉन्च

शुरुआती कीमत 28.98 लाख रुपए

गुरुग्राम। आईपीटी नेटवर्क

एमजी मोटर इंडिया ने नई दिल्ली में एक्स-शोरूम 28.98 लाख रुपए की शुरुआती कीमत पर भारत की पहली ऑटोनोमस (लेवल 1) प्रीमियम एसयूवी MG GLOSTER लॉन्च की है। अपने एलिगेंट डिज़ाइन और सम्मोहक फीचर्स के साथ GLOSTER प्रीमियम और लग्जरी क्षेत्र में अपील करता है जो 25 लाख रुपए से 50 लाख रुपए के बीच का है। यह भारत में 4 फीचर-इंटेंसिव वैरिएंट में उपलब्ध होगा, यानी सुपर, स्मार्ट, शार्प और सेवी। इसमें शानदार कॉम्बिनेशन उपलब्ध होंगे- लग्जरीयस बकेट सीट्स (6-सीटरऔर 7-सीटर), टू-व्हील ड्राइव (2WD) और फोर-व्हील ड्राइव (4WD), और ट्विन टर्बो चार्जड डीजल इंजन के साथ दो इंजन विकल्प शामिल हैं। 35.38 लाख की कीमत वाला सेवी ट्रिम अपने ऑटोनॉमस लेवल 1 फीचर्स (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम या ADAS से सक्षम है) और इंडस्ट्री-फर्स्ट कैप्टन सीट के साथ लग्जरी और टेक्नोलॉजी का सही मिश्रण देता है। इसमें फॉरवर्ड कोलिजन वॉर्निंग, ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन डिपार्चर वार्निंग, ऑटोमैटिक पार्किंग असिस्ट और एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल भी शामिल हैं। एमजी मोटर इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक राजीव चाबा ने मूल्य घोषणा पर बोलते हुए कहा, हम मानते हैं कि GLOSTER अपने सेग्मेंट में अतुलनीय लग्जरी, टेक्नोलॉजी और ऑफ-रोडिंग अनुभव के साथ नए बेंच मार्क स्थापित करेगा। अनुकूलित माय एमजी शील्ड आफ्टर-सेल्स पैकेज ग्राहकों को और अधिक विकल्प प्रदान करेंगे और उनके लिए मन की पूर्ण शांति सुनिश्चित करेंगे। ये सभी सुविधाएं हमारे ग्राहकों को उम्मीद से बढ़कर डिलीवर करने की फिलोसॉफी के अनुरूप हैं।

महाराष्ट्र में सोयाबीन फसल को नुकसान से तेल-तिलहन कीमतों में सुधार

नयी दिल्ली। एजेंसी

विदेशी बाजारों में सुस्ती के रुख के बीच महाराष्ट्र में बरसात के कारण सोयाबीन फसल को हुए नुकसान तथा मूंगफली की निर्यात मांग बढ़ने के कारण स्थानीय तेल-तिलहन बाजार में बुधवार को लगभग सभी तेलों की कीमतों में सुधार आया। बृहस्पतिवार को सीपीओ के आयात शुल्क मूल्य में वृद्धि किये जाने की संभावना के कारण इस तेल की कीमत में भी सुधार दिखा जबकि बाजार में इसकी मांग अधिक नहीं है। बाजार सूत्रों ने कहा कि मध्य प्रदेश में जहां अगस्त माह के दौरान बरसात की कमी से सोयाबीन की फसल 20-30 प्रतिशत प्रभावित हुई वहीं महाराष्ट्र में तीन-चार दिन से जारी बरसात के कारण लातूर, वासिम, नांदेड़ सहित लगभग 10 स्थानों पर सोयाबीन फसल को 25 से 30 प्रतिशत का नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि सोयाबीन फसल को हुए नुकसान और इसके तेल उत्पादन के प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए सरकारी तिलहन बिक्री करने वाली एजेंसियों को सरसों की सीमित मात्रा में बिकवाली करनी चाहिये। त्योहारी मौसम में सरसों तेल की मांग बढ़ने तथा हरियाणा और राजस्थान में नाफेड को सरसों बिक्री के लिए पहले के मुकाबले बढ़ी हुई यानी क्रमशः 5,158 रुपये और 5,352 रुपये क्विन्टल के हिसाब से बोली मिलने से सरसों तेल-तिलहनों की कीमतों में भी सुधार दर्ज हुआ। दूसरी ओर निर्यात मांग के बढ़ने से मूंगफली दाना और इसके तेल कीमतों में पर्याप्त सुधार आया। बाकी तेल तिलहनों के भाव पूर्ववत बने रहे।

इसुजु ने भारत में डी-मैक्स का बीएस-छह उत्सर्जन मानक अनुकूल संस्करण उतारा

नयी दिल्ली। इसुजु मोटर्स इंडिया ने भारतीय बाजार में अपनी डी-मैक्स पिक अप ट्रक श्रृंखला का भारत चरण-छह (बीएस-6) उत्सर्जन मानक अनुकूल संस्करण पेश किया है। इसकी मुंबई शोरूम में कीमत 7.84 लाख से 10.07 लाख रुपये है। कंपनी ने कहा कि डी-मैक्स एस-कैब ट्रिम्स का दाम 9.82 लाख से 10.07 लाख रुपये और डी-मैक्स रेगुलर कैब श्रृंखला की कीमत 7.84 लाख रुपये से शुरू होती है। कंपनी ने डी-मैक्स सुपर स्ट्रांग के रूप में एक नया संस्करण भी पेश किया है। यह उसके वाणिज्यिक वाहन खंड की अगुवाई करेगा। इस मॉडल की कीमत 8.39 लाख रुपये है। इसके साथ ही कंपनी अब अपनी डी-मैक्स श्रृंखला के तहत विभिन्न ट्रिम्स की पेशकश कर रही है, जो सभी प्रकार की कारोबारी और पेशेवर जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हैं।

Amazon.in के 'नवरात्रि शॉपिंग स्टोर' के साथ करें फेस्टिव सीजन की शुरुआत

नई दिल्ली। इस नवरात्रि, त्योहारों की शुरुआत होगी Amazon.in के 'Navratri Shopping Store' के साथ, जो पूजा सामग्री से लेकर पारंपरिक परिधान, मेकअप उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम डेकोर, किचन एप्लाएंसेस, लार्ज एप्लाएंसेस, स्मार्टफोंस, एक्सेसरीज, अमेजन डिवाइस आदि का विशेषरूप से तैयार उत्पादों का एक विस्तृत संग्रह लेकर आया है। Amazon.in पर 'नवरात्रि शॉपिंग स्टोर' की शुरुआत उपभोक्ताओं को उनके घर पर ही उनकी विशिष्ट जरूरतों के अनुरूप हजारों उत्पादों तक पहुंच उपलब्ध कराने के जरिये फेस्टिव शॉपिंग को आसान बनाने के लिए की गई है। उपभोक्ता सैमसंग, लेनोवो, रेडमी, वनप्लस, कैडबरी, फेरेरो रोचर, लकमे, मैक्स, मोची आदि जैसे बड़े ब्रांड्स के साथ फेस्टिव सीजन की तैयारियां अधिक बचत के साथ कर सकते हैं। टॉप ब्रांड्स के अलावा, 'नवरात्रि शॉपिंग स्टोर' हजारों लघु एवं मध्यम उद्यमों के उत्पादों के सबसे बड़े संग्रह को किफायती मूल्य और सुविधा के साथ पेश करेगा। आपके घर के लिए भारतीय ब्रांड्स जैसे टाइड रिबंस के फेस्टिव डेकोर प्रोडक्ट्स से लेकर लघु भारतीय विनिर्माताओं जैसे कॉटन शॉपी और लघु उद्यम आरएसके एथनिक वियर से खूबसूरत एथनिक वियर तक, आप पूरे भारत के विक्रेताओं द्वारा पेश किए जा रहे सबसे खूबसूरत फेस्टिव सिलेक्शन में से चयन कर सकते हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिये नई नीति पर मंत्रिमंडल में जल्द हो सकता है विचारः सूत्र

नयी दिल्ली। एजेंसी

केन्द्रीय मंत्रिमंडल जल्द ही नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति को मंजूरी दे सकता है। इसमें रणनीतिक क्षेत्रों को परिभाषित किया जा सकता है जिनमें चार से अधिक सार्वजनिक उपक्रम नहीं होंगे। वित्त मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सरकार ने मई में 'आत्म निर्भर भारत अभियान' पैकेज के तहत यह घोषणा की थी कि रणनीतिक क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा चार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम होंगे और अन्य क्षेत्रों में काम कर रही सरकारी कंपनियों को आखिर में निजी हाथों में दिया जायेगा। जो नई नीति घोषित होगी उसमें रणनीतिक क्षेत्रों के एक सूची तैयार की जायेगी और उन क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की कंपनियों के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र में कम से कम एक और अधिक से अधिक चार उपक्रम ही होंगे। अन्य क्षेत्रों में केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों का उनकी व्यवहार्यता के हिसाब से निजीकरण किया जायेगा। सूत्रों ने बताया कि यह मुद्दा केन्द्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष होगा और इस पर जल्द ही निर्णय किया जायेगा।

प्रवासी मजदूरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए

ऑक्सफैम इंडिया के साथ प्लैटिनम गिल्ड इंडिया ने हाथ मिलाया

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

कोविड-19 संकट ने भारत के साथ-साथ दुनिया भर में अभूतपूर्व चुनौतियां पेश की हैं और इसकी चपेट में बहुत से लोग आये हैं। हमारे समुदाय के कुछ कमजोर वर्ग, जैसे प्रवासी मजदूरों, पर इसका विशेष रूप से कठोर प्रभाव पड़ा है। प्रवासी मजदूरों की मदद करने की दिशा में कदम उठाते हुए, प्लैटिनम गिल्ड इंडिया ने ऑक्सफैम इंडिया के साथ हाथ मिलाया है, और 'प्लैटिनम सीज़न ऑफ होप' के नाम से एक पहल की शुरुआत की है। यह पहल 3 महीने की अवधि में 4500 परिवारों को प्रभावित करेगी, जिसमें लगभग 22,500 व्यक्ति शामिल रहेंगे। राहत पैकेज के 3 प्रमुख हिस्सेर हैं- दैनिक भोजन/भोजन सामग्री, सैनिटरी किट के साथ-साथ आवश्यक नॉन-फूड वस्तुओं के रूप में डायरेक्ट ट्रांसफर। यह पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा और बिहार राज्य के लोगों को राहत देगा, जहां लोग महामारी के साथ ही प्राकृतिक आपदाओं के भी शिकार हुए हैं। इस पहल के साथ, लक्ष्य यह है कि जहां सबसे अधिक आवश्यकता है, उन जगहों पर उम्मीद की ज्योति जलाई जाये।

इस पहल पर टिप्पणी करते हुए, सुश्री वैशाली बनर्जी, मैनेजिंग डायरेक्टर, पीजीआई इंडिया, ने कहा कि 'पीजीआई में, हमारा उद्देश्यर समुदाय को वापस सहयोग देने और हमारे इकोसिस्टम को एकजुट बनाये रखने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए एक आशा की किरण बनना है। इस पहल की शुरुआत करने के लिए ऑक्सफैम इंडिया से जुड़कर हम सम्मानित महसूस कर रहे हैं। वास्तव में यही कारण और उद्देश्य था, जिसकी वजह से हम इसे 'सीज़न ऑफ होप' कह रहे हैं। वैश्विक महामारी ने हमें आभारी होना सिखाया है और प्रशंसा की एक नई भावना का अहसास जगाया है। इस पहल के जरिये, उन मूल्यों और भावनाओं की तरफ लौटते हुए, जो आशावाद की भावना को जगाती हैं, हम आभार प्रकट करने की भावना को दर्शाने का लक्ष्य रखते हैं।'

ऑक्सफैम इंडिया के सीईओ, अमिताभ बेहर ने कहा कि 'हम प्लैटिनम गिल्ड इंटरनेशनल (पीजीआई) इंडिया के साथ हुई इस साझेदारी का स्वागत करते हैं। ऑक्सफैम इंडिया में, हम अपने समाज के विभिन्न वर्गों के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और लगातार उनकी बेहतरी की दिशा में सक्रिय हैं। इस वर्ष, प्रवासी मजदूर और उनके परिवार वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण सबसे अधिक प्रभावित समुदायों में से एक रहे हैं। पीजीआई इंडिया के साथ, हम समुदाय को सकारात्मक रूप से प्रभावित करना चाहते हैं और बेहतर कल के सपने को साकार करने में मदद करना चाहते हैं।'

आगामी फेस्टिव सीजन को देखते हुए

आय फाइनेंस ने MSMEs के लिए लोन देना फिर से शुरू किया

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

आरबीआई पंजीकृत एनबीएफसी आय फाइनेंस, ऐतिहासिक रूप से उपेक्षित क्षेत्र सूक्ष्म उद्यमों (माइक्रो इंटरप्राइजेज) के लिए किफायती ऋण उपलब्ध करवाता है। 2017 में मध्य प्रदेश में अपने काम की शुरुआत करने के बाद से आय फाइनेंस राज्य में लाखों सूक्ष्म उद्यमों के विकास के लिए कस्टमाइज्ड बिज़नेस लोन्स प्रदान कर रहा है। देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले तेज़ी से बढ़ते MSME क्षेत्र के लिए क्रेडिट को सुलभ बनाने के विचार से प्रेरित होकर आय फाइनेंस ने इस क्षेत्र में काम करना शुरू किया और सफलता की नई इबारत लिखी। कंपनी की पुरे मध्यप्रदेश में 12 शाखाएँ और पुरे देश में 173 शाखाएँ हैं, जहाँ 3200 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। अपनी स्थापना के बाद से, आय फाइनेंस ने 2,30,000 से अधिक सूक्ष्म उद्यमों को 3000 करोड़ रुपएसे अधिक के व्यावसायिक ऋण प्रदान किए हैं।

फेस्टिव सीजन के दौरान देश भर के सूक्ष्म-उद्यमों के लिए पर्याप्त पूंजी उपलब्ध करवाने के लिए आय फाइनेंस ने अब उस सेगमेंट को ऋण देना शुरू कर दिया है, जिसे औपचारिक रूप से ऋण देने वाले चैनलों द्वारा वर्षों से नजरअंदाज किया गया है। आय के किफायती व्यवसाय ऋण MSMEs के व्यापार की निरंतरता को बनाए रखने में मदद करेंगे, जो महामारी और उसके बाद किए गए लॉकडाउन के दौरान समाप्त हो गई थी। आय फाइनेंस के प्रबंध निदेशक संजय शर्मा ने इस सेगमेंट में फिर से लोन देने की शुरुआत करने पर कहा, 'एमएसएमई सेक्टर महामारी और समग्र आर्थिक व्यवधान के कारण सबसे ज्यादा कठिनाई से गुजरा है, ऐसे में उनके व्यवसायों को पुनर्जीवित करने के लिए आसानी से पर्याप्त पूंजी की व्यवस्था होना सबसे ज्यादा जरुरी है। इसके अतिरिक्त, त्यौहारी सीजन के दौरान मांग में वृद्धि को पूरा करने के लिए, MSMEs को अब पहले से कहीं अधिक धन की आवश्यकता है। हमारा उद्देश्य है कि जैसे-जैसे दुनिया सामान्य स्थिति में वापस आ रही है हम MSMEs को भी दोबारा अपने पैरो पर खड़ा होने में मदद करें।'

भारत में सूक्ष्म उद्यम ऋण देने के लिए आय फाइनेंस की स्थापना की गई थी और अब इन व्यवसायों को 'वित्तीय सहायता के अतिरिक्त' मदद देने के लिए गैरलाभकारी कंपनी FAME (Foundation for Advancement of Micro Enterprises) की स्थापना की है।

भारतीय अर्थव्यवस्था 2020 में 10.3 प्रतिशत घटेगी, 2021 में आयेगा 8.8 प्रतिशत का उछाल: आईएमएफ

वाशिंगटन। एजेंसी

कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित भारतीय अर्थव्यवस्था में इस वर्ष के दौरान 10.3 प्रतिशत की बड़ी गिरावट आने का अनुमान है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने मंगलवार को यह कहा। वहीं, इस दौरान विश्व अर्थव्यवस्था में 4.4 प्रतिशत की गिरावट और 2021 में 5.2 प्रतिशत की जोरदार वृद्धि के साथ आगे बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया गया है। हालांकि, इसके साथ ही आईएमएफ ने कहा है कि 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में संभवतः 8.8 प्रतिशत की जोरदार बढ़त दर्ज की जायेगी और वह चीन को पीछे छोड़ते हुये तेजी से बढ़ने वाली उभरती अर्थव्यवस्था का दर्जा फिर से हासिल कर लेगी। चीन के 2021 में 8.2 प्रतिशत वृद्धि हासिल करने का अनुमान है। आईएमएफ ने अपनी 'विश्व आर्थिक परिदृश्य' पर जारी ताजा रिपोर्ट में ये अनुमान व्यक्त किये हैं। ये रिपोर्ट आईएमएफ और विश्व बैंक की सालाना वार्षिक बैठक से पहले जारी की गई हैं। इसमें कहा गया है कि 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में 4.4 प्रतिशत की गिरावट आयेगी और 2021 में यह 5.2 प्रतिशत की जोरदार वृद्धि हासिल करेगी। आईएमएफ की इस रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में अमेरिका की अर्थव्यवस्था में 5.8 प्रतिशत गिरावट आने का अनुमान है जबकि अगले वर्ष इसमें 3.9 प्रतिशत की वृद्धि होगी। वर्ष 2020 के दौरान दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में केवल चीन ही एकमात्र देश होगा जिसमें 1.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की जायेगी। आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आर्थिक गतिविधियों के मामले में अनुमान में संशोधन भारत के मामले में बड़ा है जहां सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में दूसरी तिमाही (अप्रैल-जून, भारत के वित्त वर्ष के मुताबिक पहली तिमाही)

के दौरान अनुमान से कहीं बड़ी गिरावट रही है। रिपोर्ट में कहा गया है, "इसके परिणामस्वरूप अर्थव्यवसथा के 2020 में 10.3 प्रतिशत घटने का अनुमान है जबकि 2021 में इसमें 8.8 प्रतिशत वृद्धि के साथ बड़ा उछाल आयेगा।" इससे पहले 2019 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 4.2 प्रतिशत रही। आईएमएफ के मुताबिक जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भारत शामिल है। यह इसके शुरुआती उच्च तापमान को परिलक्षित करता है। पिछले सप्ताह विश्व बैंक ने कहा कि भारत की जीडीपी इस वित्त वर्ष में 9.6 प्रतिशत घटेगी। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया आर्थिक रिपोर्ट में यह अनुमान व्यक्त किया।

5जी परीक्षणों को लेकर उत्सुक, सरकारी नियमों का करेंगे पालन : वोडाफोन आइडिया

नयी दिल्ली। एजेंसी

दूरसंचार सेवाप्रदाता कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड 5जी प्रौद्योगिकी के परीक्षण करने के लिए 'बहुत उत्सुक' है। कंपनी ने मंगलवार को कहा कि इस मुद्दे पर वह सरकारी नीति का पूरी तरह पालन करेगी। वोडाफोन आइडिया ने मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी विशांत वोरा ने हालांकि उन वेंडर्स का नाम नहीं उजागर किया जिनके साथ कंपनी ने 5जी प्रौद्योगिकी के परीक्षण के लिए गठजोड़ किया है। लेकिन उन्होंने कहा कि कंपनी अपना आवेदन जमा करने के लिए सभी सरकारी नियमों का पालन कर रही है। वोरा ने संवाददाताओं से कहा, " मैं मीडिया में चल रही अटकलों पर टिप्पणी नहीं कर सकता। हम अपना आवेदन जमा करने के लिए सभी सरकारी नियमों का पालन कर रहे हैं। हम सरकार के साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे और निश्चित तौर पर इस मुद्दे को लेकर सरकार का जो भी फैसला होगा उसका समर्थन करेंगे।" वह एक वर्चुअल संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। यह सम्मेलन कंपनी ने अपने 'बिग डेटा' मंच को तैयार करने और रखरखाव करने की जिम्मेदारी 'आईबीएम' को देने की घोषणा करने के लिए बुलाया था। 5जी की नीलामी से जुड़े एक प्रश्न के जवाब में वोरा ने कहा, " 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी पर फैसला सरकार को लेना है। तो देखना होगा कि सरकार की नीति हमें कहां ले जाती है। लेकिन मैं कहूंगा कि भारत के लिए यह बहुत जरूरी है कि 5जी के उपयोग को लेकर वह अपने नियम बनाए ताकि यह देश की अर्थव्यवस्था और समाज के लिए मूल्यवान योगदान दे सके।" उन्होंने कहा कि जापान और चीन ने 5जी प्रौद्योगिकी को भविष्य की अर्थव्यवस्था का आधार माना है और स्पेक्ट्रम को लेकर वह इसी के अनुरूप अपनी नीतियां बना रहे हैं।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।